Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-08 16-30 अप्रैल, 2025 (पाक्षिक) ₹20

'भाजपा विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है'

'हम अपने मित्र देशों की प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं'

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 06 अप्रैल, 2025 को 'भाजपा स्थापना दिवस' के अवसर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 06 अप्रैल, 2025 को 'भाजपा स्थापना दिवस' के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करतीं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 08 अप्रैल, 2025 को भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर 'सम्मान अभियान' पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (नई दिल्ली) में 29 मार्च, 2025 को बिहार दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत मिलन' कार्यक्रम में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

गोपालगंज (बिहार) में 30 मार्च, 2025 को आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 29 मार्च, 2025 को भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

साझे भविष्य की मैत्री

06 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा और छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद 4-6 अप्रैल के बीच श्रीलंका की दो दिवसीय सफल यात्रा की। कोलंबो के भंडारनायके...

08 भारत-थाईलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 अप्रैल 2025 के दौरान थाईलैंड की आधिकारिक...

10 'विकसित भारत 2047' के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है : जगत प्रकाश नड्डा

30 मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ अप्रैल को नई दिल्ली में 7, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे...

31 'रामेश्वरम के लिए नया पंबन ब्रिज प्रौद्योगिकी और परंपरा को एक साथ लाता है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छह अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8,300 करोड़...

लेख

भारत के शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन के पीछे की सच्चाई / **धर्मेन्द्र प्रधान** 24
अटलजीः भारतीय राजनीति का निर्लिप्त कमल भाव / **बृजमोहन अग्रवाल** 26

अन्य

प्रधानमंत्री को 'श्रीलंका मित्र विभूषण' से सम्मानित किया गया 07
'एनडीए सरकार में बिहार ने विकास के नए आयाम छुए हैं' 14
बिहार की जनता तय करे कि उन्हें 'जंगलराज' की ओर जाना है या 'विकास के रास्ते' पर बढ़ना है : अमित शाह 15
'सरकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएं' 16
'सीएम ममता बनर्जी की तालिबानी तानाशाही के खिलाफ राज्य की जनता को एकजुट होने की आवश्यकता है' 17
मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब मुस्लिम ही होंगेः अमित शाह 18
इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना हैः जगत प्रकाश नड्डा 21
हम वक्फ बोर्ड्स को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बनाना चाहते हैंः किरेन रिजिजू 22
जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा और वित्तीय समावेशन का विस्तार 28
बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता क्रमशः लगभग 118 और 119 प्रतिशत रही 32
मन की बात 33
प्रधानमंत्री मोदीजी ने नागपुर स्थित रा.स्व.संघ मुख्यालय जाकर डॉ. हेडगेवार और दीक्षाभूमि जाकर डॉ. अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि 34

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

'राष्ट्र प्रथम' की भावना सर्वोपरि होने के साथ जब नीतियों और निर्णयों में देशवासियों का हित सबसे बड़ा होता है, तो सर्वत्र उसका प्रभाव भी नजर आता है।

(30 मार्च, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जिसने वैचारिक अधिष्ठान को अडिग रखा है और उसी की ताकत से आगे बढ़ रही है।

(06 अप्रैल, 2025)

अमित शाह

मोदीजी के नेतृत्व में बस्तर नक्सलमुक्त होकर विकास व विश्वास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के 'बस्तर पंडुम' में आदिवासी बहनों-भाइयों से संवाद किया।

(07 अप्रैल, 2025)

राजनाथ सिंह

रानी वेलु नचियार का जीवन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो उनकी बहादुरी और उनके त्याग की एक मिसाल देता है।

(29 मार्च, 2025)

बी.एल. संतोष

असम में एनडीए की एक और शानदार जीत। एनडीए ने राभा हसोंग स्वायत्त परिषद् चुनावों में 36 में से 33 सीटें जीतीं (भाजपा ने 6 में से 6 सीटें जीतीं)। मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा और प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप सैकिया के नेतृत्व वाली असम, भाजपा की टीम को बधाई!

(4 अप्रैल, 2025)

सुधा यादव

मुद्रा योजना ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। आज आर्थिक कारणों से कोई भी नया बिजनेस आईडिया बंद नहीं होता, बल्कि वह साकार होकर देश के निर्माण में योगदान दे रहा है।

(08 अप्रैल, 2025)

संपादकीय

सभी के साथ न्याय

भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज जब देशभर में पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जन-जन का आशीर्वाद इस गौरवमयी यात्रा को और अधिक ऊर्जावान बना रहा है। भाजपा न केवल विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल बन गया है बल्कि लोकतंत्र के ध्वज को लेकर आगे बढ़ने वाला ऐसा दल है, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र जीवंत एवं जागृत है। जहां यह 'पंचनिष्ठा' के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पंच प्रण' एवं 'विकसित भारत' के विजन से भी अनुप्राणित है। भाजपा जो सुशासन एवं विकास के लिए जानी जाती है, 'अंत्योदय' के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए अनवरत कार्य कर रही है। ऐसा इसके नेतृत्व एवं करोड़ों कार्यकर्ताओं की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता तथा केंद्र एवं विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों से प्रमाणित होता है। फलतः हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन के साथ आज भारत विश्व के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में उभरा है। विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी चमत्कारिक यात्रा में भारत ने अनेक अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त कर नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

> **भाजपा जो सुशासन एवं विकास के लिए जानी जाती है, 'अंत्योदय' के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए अनवरत कार्य कर रही है**

देश के सांसदगण जहां वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित करने के लिए बधाई के पात्र हैं, वहीं यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने अपने विभाजनकारी राजनीति के अंतर्गत इस विषय पर देश को दिग्भ्रमित करने के प्रयास किए। यह विधेयक वक्फ बोर्डों के असाधारण एवं मनमानी शक्तियों को कानूनसम्मत बनाकर वक्फ बोर्डों के प्रशासन में आवश्यक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विधेयक किसी भी संपत्ति पर दावा करने के वक्फ बोर्डों के मनमानी अधिकार को नियंत्रित करता है तथा इन बोर्डों के नियमन एवं निबंधन को व्यवस्थित करता है। ध्यान देने योग्य है कि पूर्व के वक्फ कानून एकतरफा एवं निरंकुश था, क्योंकि इससे वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति के स्वामित्व पर वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इतना ही नहीं, 2013 एवं 2014 में आम चुनावों से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने लगातार दो बार वक्फ बोर्डों को अनियंत्रित अधिकार देने के कुप्रयास किए। साथ ही, 2014 में उन्होंने वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखली) विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें आरोपियों की सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं था। इसके साथ दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में 123 अतिविशिष्ट संपत्तियों को भी चुपके से दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 से वक्फ प्रशासन में उत्तरदायित्व एवं दक्षता सुनिश्चित होगी, जिससे वक्फ प्रबंधन में आवश्यक सुधार एवं कार्यकुशलता संभव होगी। इस विधेयक से पारदर्शिता स्थापित होने के कारण समुदाय के वंचित वर्गों को सर्वाधिक लाभ पहुंचेगा तथा निहित स्वार्थी तत्वों पर अंकुश लग पायेगा। इससे मुसलमानों में गरीबों, पिछड़ों एवं महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे।

कांग्रेसनीत विपक्ष को देश में व्यापक सुधार लाने वाले हर कदम में रोड़ा अटकाने के लिए याद रखा जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर कांग्रेसनीत विपक्ष के विरोध को उनके तुष्टीकरण एवं वोट बैंक की राजनीति के व्यापक संदर्भों में देखा जाना चाहिए। यही कारण है कि इन्होंने 'तीन तलाक' पर बनने वाले कानून का भी विरोध किया तथा शाहबानो जैसी करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को दशकों तक न्याय से वंचित रखा। आज जब देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नेतृत्व में 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से 'सभी के साथ न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं' का संकल्प निश्चित ही सिद्ध होगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

साझे भविष्य की मैत्री

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (थाईलैंड) में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 अप्रैल, 2025 को कोलंबो, श्रीलंका पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री विजिता हेराथ के नेतृत्व में छह कैबिनेट मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री के होटल परिसर में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया

प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा और छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद 4-6 अप्रैल के बीच श्रीलंका की दो दिवसीय सफल यात्रा की। कोलंबो के भंडारनायके हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत हुआ।

प्रधानमंत्री ने पांच अप्रैल को श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में उपयोगी बैठक की। इस वार्ता से पहले प्रधानमंत्री का इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर रस्मी स्वागत किया गया। राष्ट्रपति श्री दिसानायका के सितंबर, 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले पहले विदेशी नेता थे।

प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंधों को और घनिष्ठ बनाने के लिए विस्तृत चर्चा

भारत की पड़ोस प्रथम नीति और विजन महासागर

दोनों नेताओं ने साझा इतिहास पर आधारित तथा जनता के बीच मजबूत संबंधों से प्रेरित विशेष और प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंधों को और घनिष्ठ बनाने के लिए सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कनेक्टिविटी, विकास सहयोग, आर्थिक संबंधों, रक्षा संबंधों, सुलह और मछुआरों के मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोस प्रथम नीति और विजन महासागर में श्रीलंका के महत्व को दोहराया। उन्होंने श्रीलंका की आर्थिक सुधार और स्थिरीकरण में सहायता के लिए भारत की ओर से निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की।

वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने कई परियोजनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन किया। इनमें श्रीलंका भर के धार्मिक स्थलों पर स्थापित 5000 सौर रूफटॉप इकाइयां और दांबुला में तापमान नियंत्रित भंडारण सुविधा शामिल है। उन्होंने 120 मेगावाट की सामपुर सौर विद्युत परियोजना के शुभारंभ के लिए भूमिपूजन समारोह में भी आभासी रूप से भाग लिया।

दोनों नेताओं की मौजूदगी में पूर्वी प्रांत में ऊर्जा, डिजिटलीकरण, रक्षा, स्वास्थ्य और बहु-क्षेत्रीय सहायता के क्षेत्रों में सात समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने त्रिंकोमाली में थिरुकोनेश्वरम मंदिर, अनुराधापुरा में पवित्र शहर परियोजना और नुवारा एलिया

प्रधानमंत्री को 'श्रीलंका मित्र विभूषण' से सम्मानित किया गया

यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका ने पांच अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'श्रीलंका मित्र विभूषण' पुरस्कार प्रदान किया। यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार किसी भारतीय नेता को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत-श्रीलंका मैत्री को मजबूत करने में उनके स्थायी योगदान के लिए प्रदान किया गया।

भारत के 1 अरब 40 करोड लोगों की ओर से पुरस्कार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और श्रीलंका के बीच विशेष मैत्री और दोनों देशों के लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों को समर्पित किया।

इस सम्मान पर आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "आज राष्ट्रपति दिसानायका द्वारा 'श्रीलंका मित्र विभूषण' से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यह सम्मान सिर्फ़ मेरा नहीं है, यह भारत के 1.4 बिलियन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। मैं इस सम्मान के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति, सरकार और लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।" ■

में सीता एलिया मंदिर परिसर के विकास के लिए सहायता देने की घोषणा की। क्षमता निर्माण और आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में सालाना अतिरिक्त 700 श्रीलंकाई नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यापक पैकेज और ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौते होने की भी घोषणा की गई। दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह के लिए गुजरात से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष श्रीलंका भेजने की घोषणा की।

भारत ने 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को अपनाया है

श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अप्रैल को कहा कि भारत ने 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में ही हमने 100 मिलियन डॉलर से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारे द्विपक्षीय 'debt restructuring एग्रीमेंट' से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने ब्याज की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है।

श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने किसानों की भलाई के लिए श्रीलंका के सबसे बड़े वेयरहाउस का भी उद्घाटन किया।

जया श्री महाबोधि मंदिर का दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ छह अप्रैल को अनुराधापुरा में पवित्र जया श्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया और पूजनीय महाबोधि वृक्ष की पूजा की।

ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष बो पौधे से विकसित हुआ है जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संगमिता महाथेरी भारत से श्रीलंका लायी थीं। यह मंदिर मजबूत सभ्यतागत संबंधों का प्रमाण है जो भारत-श्रीलंका के बीच घनिष्ठ साझेदारी की नींव है।

कोलंबो में आईपीकेएफ स्मारक का दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अप्रैल को कोलंबो में आईपीकेएफ स्मारक का दौरा किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने भारतीय शांति सेना के उन बहादुर सैनिकों की सराहना की जिन्होंने श्रीलंका की शांति, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी।

'एक्स' पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, "कोलंबो में आईपीकेएफ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। हम भारतीय शांति सेना के उन बहादुर सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने श्रीलंका की शांति, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका अटूट साहस और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।"

भारतीय मूल के तमिल नेताओं ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल (आईओटी) नेताओं ने पांच अप्रैल को कोलंबो में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत, श्रीलंका सरकार के सहयोग से आईओटी के लिए 10,000 घरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पवित्र स्थल सीता एलिया मंदिर और अन्य सामुदायिक विकास परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करेगा। ■

प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा

भारत-थाईलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 अप्रैल, 2025 को थाईलैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान श्री मोदी ने थाईलैंड द्वारा आयोजित बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) शिखर सम्मेलन में भाग लिया। थाईलैंड के उप-प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तथा बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे एवं उनके होटल पर उपस्थित रहे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 अप्रैल 2025 के दौरान थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा की और थाईलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बैंकॉक में गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री सुश्री शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया।

भारत और थाईलैंड के बीच गहरे सभ्यतागत, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों और राजनयिक संबंधों की स्थापना के 78 वर्षों को देखते हुए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, संपर्क, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री सुश्री शिनावात्रा और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऐतिहासिक लेटे हुए बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए वाट फ्रा चेतुफोन विमोन मंगखलाराम राजवरमहाविहान का भी दौरा किया।

मौजूदा सहयोग और द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि तेजी से विकसित हो रही वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर वैश्विक संदर्भ में भी निकट सहयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों

को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति प्रकट की।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

रक्षा सहयोग के मौजूदा तंत्र को मजबूत करना, साथ ही दोनों देशों के रक्षा क्षेत्रों के बीच और अधिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा उद्योग, अनुसंधान, प्रशिक्षण, आदान-प्रदान, अभ्यास और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसमें उचित तंत्र स्थापित करना शामिल है।

आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग

भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त व्यापार समिति के मौजूदा तंत्र के तहत संबंधित वाणिज्य/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच नियमित बैठकें और आदान-प्रदान आयोजित करना। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा तंत्रों की वार्षिक बैठकें सुनिश्चित करने; वैश्विक आपूर्ति शृंखला में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बाजार पहुंच के मुद्दों को हल करने के लिए भी सहमति हुई।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री मोदी का बिम्सटेक के एजेंडे और क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार अप्रैल को थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन का विषय था– 'बिम्सटेकः समृद्ध, लचीला और खुला'। प्रधानमंत्री ने म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप में जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। श्री मोदी ने दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बिम्सटेक को एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि समूह क्षेत्रीय सहयोग, समन्वय और प्रगति के लिए एक प्रभावशाली मंच बन गया है। उन्होंने बिम्सटेक के एजेंडे और क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक में संस्थान और क्षमता निर्माण की दिशा में भारत के नेतृत्व वाली कई पहलों की घोषणा की। इनमें भारत में आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के.पी. शर्मा ओली से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय और घनिष्ठ संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने भौतिक और डिजिटल संपर्क, जन-से-जन संपर्क और ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

भूटान के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन से अलग भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री तोबगे के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत और भूटान की मित्रता बहुत मजबूत है। हम कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं।"

म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार अप्रैल को बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। श्री मोदी ने हाल ही में आए भूकंप में हुई तबाही पर संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में म्यांमार के बहनों और भाइयों को भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की।

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकाक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मौके पर चार अप्रैल को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की।

श्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील एवं समावेशी बांग्लादेश के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। सीमा पर कानून का कड़ाई से कार्यान्वयन और अवैध सीमा पारगमन, विशेष रूप से रात में, पर रोक लगाना सीमा की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक है।

श्री मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारत की चिंताओं को रेखांकित किया और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिसमें उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों के मामलों की गहन जांच भी शामिल है। ■

'विकसित भारत 2047' के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 06 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस एवं श्रीरामनवमी की कोटि-कोटि शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के आरंभ में श्री नड्डा ने पार्टी ध्वजारोहण किया और तत्पश्चात् श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, श्री विनोद तावड़े, श्री अरुण सिंह एवं डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, राष्ट्रीय मंत्री श्री अनिल के. एंटनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा, नई दिल्ली लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख एवं सांसद श्री अनिल बलूनी और भाजपा राष्ट्रीय मीडिया के सह प्रमुख डॉ. संजय मयूख उपस्थित रहे।

> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ-सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जीजी और पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक राजनैतिक आंदोलन के रूप में इस सफर में भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने आप को शामिल करते हैं

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ-सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जीजी और पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक राजनैतिक आंदोलन के रूप में इस सफर में भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने आप को शामिल करते हैं। यह यात्रा 1951 में भारतीय जनसंघ नाम के राजनीतिक आंदोलन से शुरू हुई। राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह आंदोलन कुछ समय के लिए जनता पार्टी में शामिल हुआ। फिर 6 अप्रैल, 1980 को अपने वैचारिक वैशिष्ट्य को लेकर इस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया। एक नई वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति को लेकर यह आंदोलन चलता रहा। जनसंघ के दीये को अलविदा कहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कालजयी शब्दों का प्रयोग किया था और 6 अप्रैल को श्री लालकृष्ण आडवाणीजी ने एक विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी का आह्वान किया था। उन दिनों इलस्ट्रेटर वीकली और दिनमान नाम की राजनैतिक पत्रिका हुआ करती थी। आज जब भाजपा कार्यकर्ता आर्काइव्स में जाकर उस समय के लेख पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उस समय घने बादल घिरे हुए थे और किसी भी परिस्थिति में सूरज की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती थी, वैसी परिस्थिति में भी भाजपा के शीर्ष नेताओं को विश्वास था कि उनका रास्ता सही है। उसी विश्वास से ताकत लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे और इस आयाम तक पहुंचे हैं कि आज भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि संसद में विपक्षी दल भी कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज विपक्ष भी भाजपा पर कटाक्ष इस अलंकार के साथ करते हैं।

भाजपा ने एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाया

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट की खातिर कभी

समाजसेवा एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते रहेंगे: नरेन्द्र मोदी

भाजपा स्थापना दिवस (06 अप्रैल) पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "भाजपा स्थापना दिवस पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। यह महत्वपूर्ण दिन हमें भारत की प्रगति के लिए काम करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी प्रतिबद्धता पुनः याद करने का अवसर प्रदान करता है।

भारत के लोग हमारी पार्टी के सुशासन एजेंडे को देख रहे हैं, जो पिछले वर्षों में हमें मिले ऐतिहासिक जनादेश में भी परिलक्षित होता है, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हो या देश भर में विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव हों। हमारी सरकारें समाजसेवा एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती रहेंगी।

हमारी पार्टी की रीढ़, हमारे सभी मेहनती कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि वे जमीन पर सक्रिय रूप से काम करते हैं और हमारे सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता देश के हर हिस्से में चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और गरीबों, दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा एवं उत्साह वास्तव में प्रेरणादायक है।" ■

भाजपा 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ काम कर रही है : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भाजपा स्थापना दिवस पर 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, "भाजपा के स्थापना दिवस पर मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज भारतीय राजनीति की धुरी बन चुकी है। भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी और सबके विकास एवं कल्याण के प्रति समर्पित है। चाहे केंद्र सरकार हो या उसकी प्रदेश सरकारें– सभी के कामकाज में यह पूरी तरह परिलक्षित होता है।

भाजपा आज भारत की अकेली ऐसी पार्टी है जो गरीबों, दलितों, वंचितों एवं समाज के शोषित वर्गों की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि बनकर काम कर रही है। भाजपा ही वह पार्टी है जो National Aspirations के साथ ही Regional Aspirations के बीच समन्वय करना जानती है।

आज मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ काम कर रही है और देश की जनता को भी इस बात का पूरा विश्वास है कि 2047 में यह संकल्प अवश्य पूरा होगा।" ■

भाजपा 'श्रेष्ठ भारत' के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य करती रहेगी : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भाजपा स्थापना दिवस पर 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, "विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने भाजपा की नींव में देशभक्ति के बीज बोकर करोड़ों राष्ट्रभक्तों का वटवृक्ष तैयार करने का कार्य किया। मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा 'विकसित' और हर क्षेत्र में 'श्रेष्ठ भारत' के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य करती रहेगी।

चाहे श्री राम मंदिर आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाना हो, धारा 370 हटाने को अपना संकल्प बनाना हो या गरीबों, वंचितों, महिलाओं का कल्याण करना हो– भाजपा ने अपनी स्थापना से ही देशहित को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया है। अपनी चार दशकीय यात्रा में भाजपा ने यह दिखाया है कि कैसे एक राजनीतिक दल विरासतों के सम्मान, हर गरीब को आवास, अन्न, स्वास्थ्य बीमा और किसानों के कल्याण के लिए एक साथ संकल्पबद्ध रह सकता है। देश और देशवासियों की उन्नति को ही अपनी प्रगति मानने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण प्रेरणीय है।

आज मोदीजी के नेतृत्व में कमल का निशान देशवासियों के मन में विश्वास और आशा का नया प्रतीक बना है। बीते एक दशक में भाजपा ने सेवा, सुरक्षा और सांस्कृतिक जागरण के जो कार्य किए हैं, वे आने वाले दिनों में मील के पत्थर बनेंगे। भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए राष्ट्रनिर्माण में योगदान देते रहेंगे।" ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली स्थित शकुंतला आर्य जी के निवास पर पहुंचे और पार्टीध्वज फहराया

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली स्थित श्रीमती शकुंतला आर्य जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज मैं दिल्ली की पूर्व मेयर श्रीमती शकुंतला आर्य जी के निवास स्थान लाजपत नगर मंडल के बूथ संख्या 78 पर पहुंचा, भाजपा का ध्वज फहराया और उनसे सौहार्दपूर्ण मुलाकात की तथा उनका कुशलक्षेम पूछा। दिल्ली में जनकल्याण एवं विकास के नए आयाम स्थापित करने में श्रीमती शकुंतला जी का योगदान महत्वपूर्ण है। पार्टी के लिए आपकी जनसेवा एवं संघर्ष की भावना हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। यह हमारे वरिष्ठ नेताओं की लगन एवं मेहनत का ही परिणाम है कि भाजपा जनता के बीच सबसे लोकप्रिय एवं आदर्श राजनीतिक संगठन के रूप में पहचानी जाती है।" ■

डगमगाई नहीं और सत्ता को पाने के लिए कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। भाजपा एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को सदैव अडिग रखा है। 20-25 अप्रैल, 1965 के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी ने बम्बई में 'एकात्म मानवदर्शन' का व्याख्यान दिया था और जनसंघ विजयवाड़ा अधिवेशन में एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ा। इस सिद्धांत का मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि कार्ल मार्क्स के चश्मे से देखने वाले लोगों द्वारा किसी चीज को एकात्मता और समावेशिता से देखा जाना अकल्पनीय था। कांग्रेस धीरे-धीरे अपने वैचारिक क्षरण की ओर चल पड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार बनने के बाद अंत्योदय के माध्यम से इस सिद्धांत की जड़ों को मजबूत किया गया। इसी अंत्योदय को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र का पालन किया।

उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे और श्री जगन्नाथ राव जोशी जैसी महान विभूतियों की एक लंबी शृंखला भारतीय जनता पार्टी के आज दिख रहे ताज की मजबूत नींव हैं। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 1951 में भारतीय जनसंघ की यात्रा शुरू हुई, 1953 में उन्होंने 'एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे' नामक आंदोलन के साथ सत्याग्रह किया और श्रीनगर की जेल में उन्होंने संदेहास्पद स्थितियों में अपना बलिदान दे दिया। उनकी पूज्य माताजी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन नेहरू ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था जिस पर जनसंघ के लाखों कार्यकर्ताओं ने कहा था कि यह लड़ाई जारी रहेगी। 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बलिदान के दशकों बाद 6 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति के तहत भाजपा सरकार ने धारा 370 को धाराशायी कर दिया।

भाजपा ने 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम किया

श्री नड्डा ने कहा कि 1987-88 में पालमपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो शब्दशः था— 'हम राम जन्मभूमि मंदिर बनने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे' और प्रजातांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनेगा। 1987 के बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और आज रामनवमी के दिन लाखों श्रद्धालु रामलला की भव्य मूर्ति को निहार रहे हैं। भाजपा ने कभी भी पार्टी हित में नहीं, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ राष्ट्रहित में काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो केस में मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। सुप्रीम कोर्ट लगातार मुस्लिम बहनों को तीन तलाक की कुरीति से मुक्त करने की बात कहती रही, लेकिन किसी ने इस कुरीति को समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की और

1987-88 में पालमपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो शब्दशः था— 'हम राम जन्मभूमि मंदिर बनने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे' और प्रजातांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनेगा। 1987 के बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और आज रामनवमी के दिन लाखों श्रद्धालु रामलला की भव्य मूर्ति को निहार रहे हैं

इंडोनेशिया सहित सभी मुस्लिम देशों में कहीं भी तीन तलाक नहीं है लेकिन भारत में यह कुरीति जिंदा थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों को तीन तलाक की कुप्रथा के मुक्त कराया। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 22 प्रतिशत से घटकर मात्र 1.8 फीसदी रह गई है। ये लोग राजनीतिक रूप से प्रताड़ित होते रहे और जो लोग इस प्रताड़ने का कारण भारत आए, उन्हें भाजपा सरकार ने नागरिकता दी है। सभी मुस्लिम देशों में सरकारें ही वक्फ बोर्ड को चला रही हैं और भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड को सरकार के प्रशासन में लाने की बजाय सिर्फ नियमों के दायरे में ला रही है। भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी कि वक्फ बोर्ड की आय एवं संपत्ति मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और उत्थान पर लगायी जाए। भाजपा ने देश को अधिनायक वाद से बाहर निकाला है। आज राजपथ, कर्तव्य पथ बन गया, वहां श्री सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित हो गई और नौसेना के ध्वज से गुलामी के निशान हटा दिए गए। भाजपा का प्रयास सदैव से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का रहा है।

भाजपा विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी है

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के आज लोकसभा में 240 सांसद, 98 से अधिक राज्यसभा सांसद और 1600 से अधिक विधायक हैं। प्रदेशों में 13 विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, 7 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। करोड़ों कार्यकर्ताओं के योगदान से आज भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर बड़े पैमाने पर अनुसरण की जाने वाली पार्टी बनी है। आज 13.5 करोड़ से अधिक लोग भाजपा से जुड़े हैं, 10 लाख से अधिक सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता हैं, 6 लाख बूथों पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। गुजरात में छठी बार भाजपा सरकार बनी, गोवा व हरियाणा में तीसरी बार सरकार में है, मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरारा, मणिपुर व असम में दूसरी बार सरकार में हैं और 27 वर्षों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार में है। भाजपा एक मात्र ऐसी पार्टी है जो वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ी है, चुनाव जीतना, संगठन को मजबूत करना भी एक विज्ञान है। वैचारिक दृढ़ता के साथ बिना समझौता करे आगे बढ़ना ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छता अभियान से लेकर उज्ज्वला योजना तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, युवा और महिलाओं की चिंता की है। इसलिए आवश्यक है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पार्टी की नींव के रूप में कार्य करने वाले भाजपा नेताओं को पढ़ें व जानें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना 'विकसित भारत 2047' को पूरा करने के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री नड्डा ने कहा कि 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक भाजपा का एक-एक नेता एवं कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्तियों में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की अलख जगाएंगे। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 25 तक संविधान गौरव दिवस भी मनाया जाएगा और संविधान निर्माण में बाबासाहेब के योगदान से लोगों को अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान की मूल आत्मा पर कुठाराघात किया है, भाजपा उसका भी पर्दाफाश करेगी। श्री नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि बूथ पर जाने का दौरान जनसंघ और भाजपा के स्थापना काल के कार्यकर्ताओं को ढूंढकर उनके घर जाएं।

प्रमुख बिंदु

- 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक भाजपा का एक-एक नेता एवं कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्तियों में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की अलख जगाएगा
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ-सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जीजी और पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा है
- आज 13.5 करोड़ से अधिक लोग भाजपा से जुड़े हैं, 10 लाख से अधिक सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता हैं, 6 लाख बूथों पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं
- भाजपा वोट के खातिर इधर से उधर नहीं डगमगाई, सत्ता पाने के लिए विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। भाजपा एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिसने वैचारिक अधिष्ठान को अडिग रखा है और उसी की ताकत से आगे बढ़ रही है
- 1953 में श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बलिदान को सार्थक करते हुए 6 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति के तहत भाजपा सरकार ने धारा 370 को धाराशायी कर दिया
- राजीव गांधी सरकार ने शाह बानो केस में मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे अपने घुटने टेक दिए थे लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों को तीन तलाक की कुप्रथा के मुक्त कराया
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत व स्वच्छता अभियान से लेकर उज्ज्वला योजना तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, युवा और महिलाओं की चिंता की है
- वक्फ बोर्ड को सरकार नियमों के दायरे में लाकर भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति और आय मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और उत्थान पर लगे

'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' स्नेह मिलन समारोह

'एनडीए सरकार में बिहार ने विकास के नए आयाम छुए हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 मार्च, 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन समारोह' को संबोधित किया और बिहार को विश्व को प्रजातंत्र की सीख देने वाली भूमि बताया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली से लोकसभा सांसद श्री मनोज तिवारी, सुश्री बांसुरी स्वराज एवं श्रीमती कमलजीत सहरावत, दिल्ली प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद तथा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रत्यूष कंठ सहित पार्टी के कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। श्री नड्डा ने सभी उपस्थितजनों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा बिहार की संस्कृति, परंपरा और विकास में योगदान देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उन्होंने भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष श्री संतोष ओझा को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों से एकजुटता और बिहार एवं देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

श्री नड्डा ने बिहार की स्थानीय कलाओं एवं हस्तशिल्प की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। बिहार के शिल्पकारों और कलाकारों ने अपने हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिसमें मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, टिकुली आर्ट, सीकरी पेंटिंग और सूत शिल्प जैसे अद्वितीय हस्तशिल्प शामिल थे। उन्होंने कहा कि बिहार की कला और संस्कृति भारतीय विरासत का अभिन्न अंग है और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भाजपा सरकार हरसंभव सहयोग कर रही है।

उन्होंने कहा कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश आगे बढ़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि विश्व को प्रजातंत्र की सीख भी बिहार की भूमि से मिली है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपना पहला आंदोलन भी बिहार के चंपारण से ही शुरू किया था और जब लोकतंत्र पर कांग्रेस की सरकार में कुठाराघात हो रहा था, तब भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती से ही शुरू किया था। इसलिए बिहार का एक विशेष महत्व है। विश्वभर के प्रजातंत्र का तंत्र बिहार की ही धरती से ही विकसित हुआ है। बिहार तेजस्विता और कर्मशीलता के साथ खड़ा होने की ताकत रखता है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर विद्यमान थे और देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से विद्यार्थी वहां विद्या ग्रहण करने आते थे। दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमें मैथिली, मगही या भोजपुरी बोलने वाले मिल जाएंगे। ईमानदारी से अपने काम को करने की ताकत इसी बिहार की धरती के लोगों में हैं।

आरजेडी पर करारा हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आगे बढ़ते हुए बिहार को लालूराज ने डूबता हुआ बिहार बना दिया था। एक समय ऐसा आया था कि शाम 5 बजे के बाद लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन एनडीए की सरकार में बिहार ने विकास के नए आयाम छुए हैं। मेरा बचपन और किशोरावस्था बिहार में ही बीता है। अपने बचपन के दौरान मैंने गंगा किनारे गांधी सेतु को बनते हुए देखा है, निर्माण कार्य कई दशकों तक चलता रहा। आज बिहार में गंगा किनारे मरीन ड्राइव बन चुका है, इसके ऊपर से नया पुल बन चुका है। बिहार में सड़कों और रेल नेटवर्क का जाल बुना गया है।

> महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपना पहला आंदोलन भी बिहार के चंपारण से ही शुरू किया था और जब लोकतंत्र पर कांग्रेस की सरकार में कुठाराघात हो रहा था, तब भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती से ही शुरू किया था

उन्होंने कहा कि जब 2005 में बिहार में एनडीए सरकार आई थी, तब बिहार में ग्रामीण सड़क का नेटवर्क केवल 384 किमी का था, जबकि आज बिहार में 1 लाख 12 हजार किमी सड़क बन चुकी है।

श्री नड्डा ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन राज्य में जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से विजयी होगी तथा वहां विकास की गति और तेज होगी। ■

विशाल जनसभा, गोपालगंज (बिहार)

बिहार की जनता तय करे कि उन्हें 'जंगलराज' की ओर जाना है या 'विकास के रास्ते' पर बढ़ना है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 मार्च, 2025 को बिहार के गोपालगंज में आयोजित विशाल जनसभा संबोधित करते हुए विगत 10 वर्षों में बिहार के लोगों और युवाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए जनकल्याण एवं विकास कार्यों का उल्लेख किया और आरजेडी के जंगलराज पर जमकर हमला बोला। श्री शाह ने कहा कि लालू यादव ने केवल अपने परिवार को सेट किया और बिहार युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बिहार को विकसित करने का काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार दिया। श्री शाह ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े, उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश, सांसद डॉ. संजय जयसवाल, सांसद व वरिष्ठ नेता श्री राधामोहन सिंह, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी डॉ. संजय मयूख सहित अन्य नेतागण मंच पर उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि इस साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बिहार की जनता को यह तय करना है कि उन्हें लालू-राबड़ी के 'जंगलराज' की ओर जाना है या प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दस वर्षों में विकास कार्यों को बिना रुके आगे बढ़ाया है।

> **बिहार में 'माता सीता' का भव्य मंदिर बनेगा और पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा, जो मातृशक्ति का संदेश देगा**

उन्होंने कहा कि सिर्फ बुनियादी विकास ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी होगा। बिहार में 'माता सीता' का भव्य मंदिर बनेगा और पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा, जो मातृशक्ति का संदेश देगा। अयोध्या-जनकपुर रामायण सर्किट बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देगा। वैशाली महोत्सव की शुरुआत की गई है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया। मोदी सरकार ने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को पद्म भूषण दिया था और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि 15 साल तक बिहार में लालू-राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक केंद्र की सोनिया-मनमोहन सरकार में लालू यादव केंद्रीय मंत्री रहे। लालू यादव बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? 2004-05 में बिहार का बजट 23 हजार करोड़ रुपये था, जिसे एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3 लाख 23 हजार करोड़ रुपये किया। प्रति व्यक्ति आय 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 66 हजार रुपये की गई। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, जो 56% थी, उसे घटाकर 33% तक लाया गया।

श्री शाह ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, तब बिहार को रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती और अराजकता में धकेल दिया गया था। आरजेडी शासन में घोटाले ही घोटाले किए गए। अलकतरा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, रेलवे होटल घोटाला, मिट्टी घोटाला और चारा घोटाला हुआ। आरजेडी के नेता गौ माता का चारा भी खा गए। इन लोगों को न शर्म आई, न ही लाज। बिहार के लोग फिर से अपहरण, हत्या और भय के शासन में नहीं जाना चाहते हैं। बिहार की जनता चारा घोटाले को कभी नहीं भूल सकती है और न ही बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश को भुलाया जा सकता है। बिहार के युवा नौकरी के बदले जमीन का षड्यंत्र को नहीं भूल सकते हैं। लालू यादव जी ने केवल अपने परिवार को सेट किया है। उनके दोनों बेटे आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद हैं, दूसरी बेटी को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। उनकी पत्नी राबड़ी देवीजी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। लालू यादवजी ने अपनी भाभी को भी नेता बनाया और उनके भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा, लालू जी ने सभी को सेट कर दिया। लालू यादवजी ने अपने परिवार को तो आगे बढ़ाया, मगर बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन यह काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं।

श्री शाह ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की और बिहार को एक बार पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। ■

'सरकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएं'

भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने 29 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से तीन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें जीईएम (GeM) पोर्टल, कमल मित्र एवं 'सेल्फी विद लाभार्थी' पहल शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसी महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

जीईएम पोर्टल पहल के तहत 1,41,000 महिला उद्यमियों को पंजीकृत किया गया। 'सेल्फी विद लाभार्थी' अभियान में 10,000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया और कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल 80 सफल महिलाओं को सम्मानित किया गया। 'कमल मित्र' कार्यक्रम के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, इन सभी को महिला कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद यह प्रशिक्षित महिलाएं अपने-अपने राज्यों में जाकर अन्य महिलाओं को शिक्षित कर रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके। कमल मित्र पहल के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर, शोधकर्ता एवं व्यवसायी महिलाएं जुड़ी है, जिन्होंने महिला मोर्चा सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया। इन तीन पहलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण देने वाली महिलाओं को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पांडा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष, भाजपा राष्ट्रीय संगठक श्री वी. सतीश, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष श्री के. अन्नामलाई, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन एवं अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

जीईएम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद महिलाओं के कारोबार में वृद्धि आयी

इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष ने जीईएम पोर्टल पंजीकरण, कमल मित्र एवं ' सेल्फी विद लाभार्थी ' पहल में महिलाओं के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सरकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात का आकलन करने का आह्वान किया कि जीईएम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद इन महिलाओं के कारोबार के विकास में किस तरह का सहयोग मिला है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने एक ऐसे संगठन का हिस्सा होने पर गर्व व्यक्त किया जिसने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया। उन्होंने महिला मोर्चा की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जनसंघ की संस्थापक सदस्य राजमाता विजया राजे सिंधिया के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

रानी वेलु नचियार: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने वाली दक्षिण भारत की पहली रानी

महिला मोर्चा द्वारा आयोजित दूसरे कार्यक्रम में रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि दी गई, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने वाली दक्षिण भारत की पहली रानी थीं। नाट्य प्रदर्शनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान एवं संघर्ष को दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त एक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया गया, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का दस्तावेजीकरण किया गया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी एवं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन शामिल हुई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रानी वेलु नचियार की अद्वितीय बहादुरी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में अग्रणी भूमिका की सराहना की। उन्होंने देश की अखंडता के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को याद करने और उनका सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता पर प्रकाश डाला। एक ओर जहां उन्होंने रानी वेलु नचियार के नेतृत्व तथा भारत के रक्षा एवं शासन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला, वहीं उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए चल रही प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।

उन्होंने समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से नेतृत्व को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी वीरता की कहानियां भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। ■

पश्चिम बंगाल : शिक्षक भर्ती घोटाला

'सीएम ममता बनर्जी की तालिबानी तानाशाही के खिलाफ राज्य की जनता को एकजुट होने की आवश्यकता है'

भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. संबित पात्रा ने 04 अप्रैल, 2025 को केन्द्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को खारिज करने व कोर्ट के निर्णय का विरोध करने को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की। डॉ. पात्रा ने नैतिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि टीएमसी प्रमुख एवं सीएम ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी भी आधार पर मानने से इन्कार करना पूरी तरह तानाशाही और हिटलरशाही है।

डॉ. पात्रा ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2016 से 2021 के बीच हुए स्कूल भर्ती घोटाले पर टिप्पणी की है। पश्चिम बंगाल में विज्ञापन के माध्यम से निकली टीचर और नॉन-टीचिंग स्टाफ की पोस्ट पर लगभग 23 से 24 लाख एप्लिकेंट्स ने आवेदन किया था। 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। उसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर कई लोग कोर्ट में गए और उस समय बंगाल में इसे 'ब्राइब फॉर जॉब स्कैम/ नौकरी के लिए रिश्वत घोटाला' और 'स्कूल भर्ती घोटाले' के नाम से जाना गया। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक स्पष्ट निर्णय देते हुए कहा कि यह जो 25,780 नियुक्तियां हुई हैं, यह भर्ती प्रक्रिया दोषपूर्ण है और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। पैसे लेकर गलत तरीकों से ओएमआर शीट को नष्ट कर दिया गया, ताकि यह पता न चले कि कौन सही है और कौन गलत। ताकि, जो सबसे नीचे के पायदान पर था, उस उम्मीदवार को ऊपर लाकर उच्च रैंक में स्थापित किया जा सके। जो टॉपर नहीं था, उसे टॉपर बना दिया गया। जिसने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, जिसने ओएमआर शीट में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसे भी पैसे के बल पर नियुक्ति पत्र दे दी गई।

उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, जब हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट में 126 अप्लिकेंट अपनी ऐप्लिकेशन दायर करने के गए थे कि हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज किया जाए। उनमें से एक अप्लिकेंट वेस्ट बंगाल की सरकार भी थी। ममता सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट गलत बोल रहा है। ये कोर्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना चाहता है, तो कोर्ट के इस फरमान को खारिज कर दिया जाए।" सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे ऑर्डर दिया। इसके बाद इस मामले में पूरी जांच हुई और कल सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार दोनों ने अपना फैसला सुनाया। आदेश के एक अंश में कहा गया है कि हमने इस केस के तथ्यों को जांच की है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वह पूरी तरह से भ्रष्ट है, फ्रॉड है और धोखाधड़ी है। विश्वसनीयता की धज्जियां उड़ गई हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. पात्रा ने कहा कि आज कितने लोग रो रहे हैं, कितने शिक्षक रो रहे हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है। अभी लगभग 26,000 लोगों को नौकरियों से निकाले जाएंगे, उनके जीवन पर क्या गुजर रही होगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने यह सारी घपलेबाज़ी, घोटालेबाज़ी की है, इसलिए आज लाखों लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से मांग की है कि जिन 25,750 लोगों की तनख्वाह बंद होगी, ममता बनर्जी टीएमसी के फंड से या सीएम रिलीफ फंड से उनका भरण-पोषण करें और उन्हें सैलरी दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पश्चात् सीएम ममता बनर्जी ने मानवीय पक्ष की बात की, उन्होंने कहा कि ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड पर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती और मैं यह फैसला खारिज करती हूं। भाजपा का सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों पर स्वतः संज्ञान लें और ममता बनर्जी व तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मामला चलाए जाए।

> टीएमसी प्रमुख एवं सीएम ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी भी आधार पर मानने से इन्कार करना पूरी तरह तानाशाही और हिटलरशाही है

डॉ. पात्रा ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की इस तालिबानी तानाशाही वाले शासन के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल की जनता को एकजुट होने की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार ने कहा जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पैसे लेकर नौकरियां बेचीं, उन्हें ममता बनर्जी ने बचाया। कैबिनेट की बैठक करके स्कूलों में जहां 1,000 शिक्षकों की ज़रूरत थी, वहां 1,500 अतिरिक्त पद सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए बनाए गए, जिन्होंने घूस देकर नौकरियां पाई थीं। यह एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल शामिल था। ■

मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब मुस्लिम ही होंगे: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दो अप्रैल को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर चर्चा में हिस्सा लिया

चर्चा में भाग लेते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका इतिहास हदीसों से जुड़ा हुआ है। आजकल जिस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान या पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। उन्होंने कहा कि वक्फ का समकालीन अर्थ इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री ओमर के समय में अस्तित्व में आया। आज की भाषा में वक्फ एक प्रकार का Charitable Endowment है, जहां कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए संपत्ति दान करता है। इसमें दान निजी चीज का ही किया जा सकता है। सरकारी संपत्ति या किसी और की संपत्ति का दान नहीं कर सकते।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से जुड़े कार्यों में किसी गैर-इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन में गैर-मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान नहीं है और हम ऐसे प्रावधान करना भी नहीं चाहते। श्री शाह ने कहा कि विपक्ष भ्रांति फैला रहा है कि यह विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में दखल के लिए लाया जा रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यक समुदाय को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने की कोशिश कर रहा है।

वक्फ वही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो

गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड या इसके परिसरों में जिन गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा, उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करेंगे कि दान से संबंधित मामलों का प्रशासन नियम के अनुरूप हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि वक्फ भारत में ट्रस्ट की तरह है। ट्रस्ट में ट्रस्टी और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ और मुतवली होते हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होते हैं। श्री शाह ने कहा कि वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए वक्फ वही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। उन्होंने कहा कि वक्फ धार्मिक चीज है, लेकिन वक्फ बोर्ड या वक्फ परिसर धार्मिक नहीं हैं। कानून के मुताबिक चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं चलाना। उसे यह सुनिश्चित करना है कि चैरिटी कानून के हिसाब से बोर्ड का संचालन हो। श्री शाह ने कहा कि यह धर्म का नहीं, प्रशासन का काम है।

श्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालों को पकड़कर बाहर निकालने का होना चाहिए। उसे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने वक्फ के नाम पर औने-पौने दाम में संपत्तियों को सौ-सौ साल तक किराए पर दे रखा है। उन्होंने कहा कि वक्फ की आय कम होती जा रही है, जबकि वक्फ के पैसे से अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होना चाहिए और इस्लाम धर्म

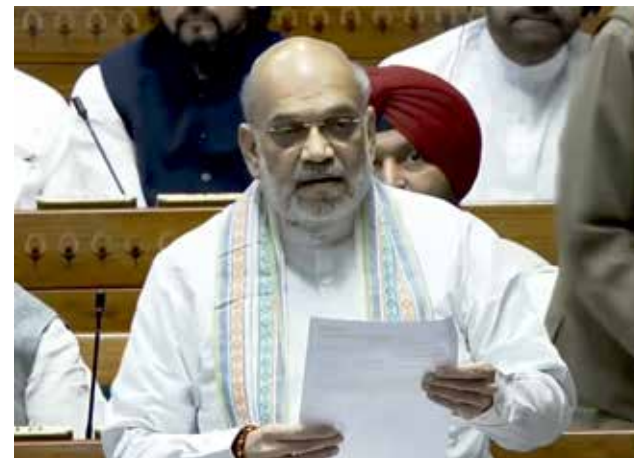

अगर 2013 में वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया होता, तो इस विधेयक को लाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन 2014 में चुनाव से पहले 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण की खातिर वक्फ कानून को Extreme बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली में लुटियन्स ज़ोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई

की संस्थाओं को पुख्ता किया जाना चाहिए। इस पैसे की चोरी पर रोक लगाना ही वक्फ बोर्ड और उसके परिसर का काम होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है उनके राज में चलने वाली मिलीभगत चलती ही रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अगर 2013 में वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया होता, तो इस विधेयक को लाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन 2014 में चुनाव से पहले 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण की खातिर वक्फ कानून को Extreme बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली में लुटियन्स ज़ोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम कर दी। वहीं, हिमाचल प्रदेश में वक्फ की संपत्ति बताकर उस जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया गया। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदूर मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार 29,000 एकड़ वक्फ भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दी गई। वर्ष 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य

की वक्फ संपत्ति निजी संस्थानों को 100 साल की लीज पर सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाड़ 602 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रोका गया। विजयपुर, कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि को विवादित बनाकर 500 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन को फाइव-स्टार होटल को मात्र 12,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दे दिया गया।

श्री अमित शाह ने कहा कि यह सारा पैसा गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए है, न कि धनकुबेरों की लूट के लिए। कर्नाटक में दत्तापीठ मंदिर पर दावा किया गया। तालीपरंबा में 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई। ईसाई समुदाय की संपत्तियों पर भी कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि देश के कई चर्चों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्योंकि वे इसे मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति जीतने का जरिया मानते हैं। लेकिन चार साल में मुस्लिम भाइयों को भी पता चल जाएगा कि यह विधेयक तो उनके फायदे का है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तेलंगाना में 66 हजार करोड़ रुपए की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया, वहीं असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा किया गया। गुरुद्वारे से संबंधित हरियाणा की चौदह मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया और प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के वडांगे गांव में महादेव के मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली।

वक्फ के पास लाखों-करोड़ों रुपए की भूमि है, लेकिन आय सिर्फ 126 करोड़ रुपए

श्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से जुड़े ट्रस्ट यानी वक्फ में सरकार कोई दखल नहीं करना चाहती। मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब उनके ही होंगे, परन्तु यह जरूर देखा जाएगा कि वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है या निजी उपयोग के हिसाब से हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह की दान की गई संपत्ति को 12 हजार रुपए के मासिक किराये पर पांच सितारा होटल बनाने के लिए देना कहां तक उचित है। वह पैसा गरीब मुसलमानों, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों, बेरोजगार मुसलमानों के भलाई और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास लाखों-करोड़ों रुपए की भूमि है, लेकिन आय सिर्फ 126 करोड़ रुपए है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब 2013 का संशोधन विधेयक पेश किया था, उस समय सरकार में रहे वरिष्ठ नेताओं ने वक्फ

मुख्य बातें

- विपक्ष भ्रांति फैला रहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में दखल है
- मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से जुड़े ट्रस्ट यानी वक्फ में सरकार कोई दखल नहीं करना चाहती
- मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब मुस्लिम ही होंगे, परन्तु यह जरूर देखा जाएगा कि वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं
- वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से जुड़े कार्यों में किसी गैर-इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं मिलेगी
- वक्फ बोर्ड या इसके परिसरों में जिन गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा, उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा
- वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालों को पकड़कर बाहर निकालने का होना चाहिए
- वर्ष 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण की खातिर वक्फ कानून को Extreme बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली में लुटियन्स ज़ोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई
- मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है
- सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, लेकिन लोभ, लालच और भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता
- वक्फ पर संसद द्वारा बनाया जा रहा कानून, भारत का कानून है, इसे सभी को स्वीकारना होगा
- 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 तक और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई
- लीज़ पर दी गई संपत्तियां 20 हज़ार थीं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गईं, ये संपत्तियां बेच दी गईं
- यह विधेयक ज़मीन की सुरक्षा प्रदान करेगा, किसी की ज़मीन घोषणा मात्र से वक़्फ़ नहीं बनेगी और उसे सुरक्षा मिलेगी
- दान केवल अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, सरकारी या किसी और की संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता
- राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक़ और CAA के समय भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि भय की कोई बात नहीं है
- दो साल हो गए CAA से किसी की नागरिकता नहीं गई, अगर CAA से किसी की नागरिकता गई है तो विपक्ष उसकी जानकारी सदन के पटल पर रखे

की संपत्ति की लूट-खसोट रोकने के लिए कड़े कानून बनाने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की वकालत की थी। श्री शाह ने कहा कि मौजूदा विधेयक से पारदर्शी ऑडिट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने संशोधन में लिखा था कि वक्फ बोर्ड के ऑडर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सच यह है कि इसे अदालत में चुनौती देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक retrospective effect से लागू नहीं होगा, लेकिन विपक्ष द्वारा मुस्लिमों को डराया जा रहा है।

श्री शाह ने वक्फ से जुड़े विधेयक में जिला कलेक्टर की भूमिका पर कहा कि देश में जब किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी होती है तो कलेक्टर ही यह तय करता है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। उन्होंने कहा कि फिर वक्फ की भूमि की जांच कलेक्टर द्वारा किए जाने पर आपत्ति क्यों है? गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ की भूमि सरकारी है या नहीं, इसे कलेक्टर ही सत्यापित कर सकता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है। इसी सदन में मोदी सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लाई और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, लेकिन लोभ, लालच और भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता।

नरेन्द्र मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है। इसी सदन में मोदी सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लाई और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया

श्री शाह ने कहा कि 2013 में लाए गए संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में कुल मिलाकर साढ़े 5 घंटे चर्चा हुई जबकि इस बिल पर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने संयुक्त समिति बनाई, 38 बैठकें हुईं, 113 घंटे चर्चा हुई और 284 हितधारक बनाए गए। इन सबसे देशभर से लगभग एक करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए जिनकी मीमांसा कर यह कानून बनाया गया और इसे ऐसे खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है यहां किसी एक परिवार की नहीं चलती है। सांसद जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं और वे जनता की आवाज़ को रखेंगे।

यह भारत सरकार का कानून है जो सब पर बाध्य है

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह देश की संसद द्वारा बनाया गया कानून है जिसे सबको स्वीकारना पड़ेगा। यह भारत सरकार का कानून है जो सब पर बाध्य है और सभी को इसे स्वीकारना होगा। उन्होंने कहा कि 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 के बीच 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। इस 39 लाख एकड़ भूमि में 21 लाख एकड़ भूमि 2013 के बाद की है। श्री शाह ने कहा कि लीज़ पर दी गई संपत्तियां 20 हज़ार थीं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गईं। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां बेच दी गईं। गृह मंत्री ने कहा कि कैथौलिक और चर्च संगठनों ने इस कानून को अपना समर्थन दिया है और 2013 के संशोधन को अन्यायी बताया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक ज़मीन की सुरक्षा प्रदान करेगा, किसी की ज़मीन घोषणा मात्र से वक्फ़ नहीं बनेगी और उसे सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ज़मीन को सुरक्षा देंगे और शेड्यूल 5 और 6 के अनुसार आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही आम नागरिक की निजी संपत्ति भी सुरक्षित हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि दान तो सिर्फ़ अपनी संपत्ति का ही किया जा सकता है इसीलिए स्वामित्व के बिना वक्फ़ निजी संपत्ति नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ़ अधिनियम में सूचना देने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ़ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और अब इसे कलेक्टर से सत्यापित करवाना होगा। इसके साथ ही नए वक्फ़ का पारदर्शी तरीक़े से पंजीकरण भी करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम भी वक्फ़ ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत अपना ट्रस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि इसके लिए वक्फ़ क़ानून ज़रूरी नहीं है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना का फ़ैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर, ट्रिपल तलाक़ और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के समय भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि भय की कोई बात नहीं थी। गृह मंत्री ने कहा विपक्ष कहता था कि CAA से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन दो साल हो गए किसी की नागरिकता नहीं गई। उन्होंने विपक्ष से कहा कि अगर CAA से किसी की नागरिकता गई है तो वह उसकी जानकारी सदन के पटल पर रखे। श्री शाह ने कहा कि धारा 370 हटाने पर भी मुसलमानों को डराने का प्रयास किया गया, लेकिन आज वहां एक निर्वाचित सरकार है, आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया और पर्यटन बढ़ गया।

श्री शाह ने कहा विपक्षी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने मुसलमान भाइयों को डरा-डरा कर अपनी वोटबैंक खड़ी करने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का यह संकल्प है कि इस देश के किसी भी नागरिक पर, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कोई आंच नहीं आएगी। ■

इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 अप्रैल, 2025 को राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उसे सुव्यवस्थित करना है। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन का सारांशः

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने सदन को संबोधित करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रति अपना प्रबल समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस विधेयक का उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उसे सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि सरकार विधेयक को 'धकेल रही है', उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया समावेशी और पारदर्शी रही है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और हितधारक सहभागिता

श्री नड्डा ने विधेयक के निर्माण के दौरान अपनाई गई व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की तुलना यूपीए काल से की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में 31 सदस्य शामिल थे (जबकि 2013 में यूपीए के अंतर्गत 13 सदस्य थे) और 200 घंटों से अधिक समय तक 36 बैठकें हुईं। उन्होंने आगे कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया, जिसमें 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड, 15 राज्य सरकारें, अल्पसंख्यक आयोग, सांसद, विधायक और मंत्री सहित 284 हितधारक शामिल थे।

विपक्ष की रणनीति की आलोचना

श्री नड्डा ने विपक्षी सदस्यों पर राम मंदिर, कुंभ मेला, बिहार चुनाव और केरल सिनेमा जैसे अप्रासंगिक विषयों को चर्चा में लाकर बहस को पटरी से उतारने का आरोप लगाया, जिनका विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने विपक्ष की चालों की ओर भी इशारा किया, जैसेकि विधेयक के दायरे से बाहर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करना। उन्होंने सनसनीखेज और चर्चा का राजनीतिकरण करने के प्रयासों की निंदा की और पक्षपातपूर्ण एजेंडे के बजाय राष्ट्रीय हित पर ध्यान देने का आग्रह किया।

राष्ट्रीय हित और उत्तरदायित्व

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व श्रेणी (रेलवे और रक्षा के बाद) है। उन्होंने कहा कि 2013 अधिनियम के तहत वक्फ बोर्डों को दी गई अनियंत्रित शक्तियों के कारण मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन सहित दुरुपयोग हुआ। संशोधन का उद्देश्य जांच और संतुलन स्थापित करना है, यह सुनिश्चित करना कि वक्फ बोर्ड जनता, विशेष रूप से मुस्लिम समुदायों के प्रति जवाबदेह हो।

उन्होंने समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' और 'आवास योजना' जैसी योजनाओं का हवाला दिया तथा इस बात पर जोर दिया कि इसका लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों तक पहुंचे।

वक्फ सुधारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मिसाल

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधेयक की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए मुस्लिम बहुल देशों में सुधारों पर प्रकाश डाला। उदाहरण के लिएः

क. तुर्कीए ने 1924 में राज्य-नियंत्रित वक्फ प्रबंधन की स्थापना की तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया।

ख. मलेशिया वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए भू-मानचित्रण और आधुनिक वित्तीय मॉडल का उपयोग करता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होती है।

ग. सऊदी अरब और इंडोनेशिया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः 2016 और 2004 में वक्फ कानूनों में सुधार किया था।

इन उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि भारत में इसी तरह के सुधारों की आलोचना क्यों की जाती है। उन्होंने

शेष पृष्ठ १३ पर...

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया

हम वक्फ बोर्ड्स को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बनाना चाहते हैं: किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने दो अप्रैल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के बाद लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस बार संयुक्त समिति में वक्फ संशोधन विधेयक पर भारत के संसदीय इतिहास में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हुई है। कुल मिलाकर 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वैस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में आई हैं। सरकार ने उनको पूरी तरह से देखा है, चाहे वह जेपीसी के माध्यम से आई हो या डायरेक्ट दिया गया हो। आज तक इतनी ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर लोगों की याचिकाएं नहीं आई हैं। कुल मिलाकर 284 डेलिगेशन्स ने समिति के सामने अपनी बात को रखा है और सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के वक्फ बोर्ड ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद वर्ष 1954 में वक़्फ़ अधिनियम पहली बार आज़ाद भारत का अधिनियम बना। उस समय वर्ष 1954 के अधिनियम में स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर कई संशोधनों के साथ वर्ष 1995 में व्यापक रूप से यह वक़्फ़ अधिनियम बना है। उस समय किसी ने नहीं कहा कि यह गैर-कानूनी है। वर्ष 1995 में पहली बार ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की गई है, ताकि वक़्फ़ बोर्ड का कोई भी निर्णय अगर किसी को पसन्द नहीं है, अगर वह उसको चैलेंज करना चाहता है, तो वह वक़्फ़ ट्राइब्यूनल में जा सकता है।

वर्ष 2013 में कुछ ऐसे कदम उठाये गये, जिसे सुनकर दिमाग में यह सवाल जरूर उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया था। वर्ष 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो या जैन हो, वक़्फ़ क्रिएट कर सकता है। सबको यह मालूम है कि अल्लाह के प्रति एक पवित्र, धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्य के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसे शिथिल करके वर्ष 2013 में उस समय की यूपीए सरकार ने यह प्रावधान किया कि कोई भी वक़्फ़ क्रिएट कर सकता है।

हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक है

वक्फ बनाने के संबंध में हमारी सरकार ने वर्ष 1995 के प्रावधानों को फिर से रिवाइव करते हुए यह जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है, जो मिनिमम पांच साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। हम वक्फ बोर्ड्स को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बनाना चाहते हैं। इसलिए इसमें पिछड़े मुस्लिम लोग, महिलाएं और एक्सपर्ट नॉन-मुस्लिम को शामिल करने का भी प्रावधान रखा गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 22 मेंबर्स में से चार नॉन-मुस्लिम से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। दस मुस्लिम सदस्यों में से दो महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इसी तरह से स्टेट बोर्ड में 11 मेंबर्स में 3 से ज्यादा नॉन-मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। चार मुस्लिम सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी।

आर्बिट्ररी प्रोविजंस और इनसफिशिएंट प्रोविजन के स्थान पर हमने नया प्रावधान लाया है। हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक है। जब दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों की पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेट, स्किलिंग, इनकम जेनरेशन के लिए आज तक क्यों काम नहीं हुआ? उस प्रॉपर्टी से गरीबों के उत्थान और लोगों की भलाई करने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया जाना है और इसके लिए आज इस वक्फ संशोधन बिल की जरूरत है। वर्ष 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज से कुल आय 163 करोड़ रुपये थी और आज यह इनकम 166 करोड़ रुपये है। अगर 10 सालों के बाद भी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ रुपए बढ़ती है, तो इसे हम कभी भी मंजूर नहीं कर सकते हैं।

सच्चर कमेटी के समय भी कहा गया था कि अगर इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा भी कुशलता से मैनेज करते तो 12 हजार करोड़ रुपये प्रति साल उस समय जेनरेट हो जाना चाहिए था। आज 4.9 लाख से बढ़कर हमारे देश में कुल वक्फ प्रॉपर्टीज 8.72 लाख हो गयी है। यदि 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इससे मुसलमानों के साथ-साथ देश की तकदीर बदल जाएगी। जेपीसी की कई सिफारिशों को इस विधेयक में शामिल किया गया है।

यह कहना ठीक नहीं है कि संयुक्त संसदीय समिति की बात को नहीं माना गया है। विधेयक को लेकर सबके मन में उम्मीद जगी है, इसलिए इस विधेयक का नाम 'उम्मीद अर्थात यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पॉवरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया है। इस अधिनियम से मुसलमानों में भी जो शिया है, सुन्नी हैं, बोहरा हैं, आगाखानी, पसमांदा मुस्लिम्स हैं, जिनको बैकवर्ड माना

जाता है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हमने जो प्रावधान रखे हैं, सबका सशक्तीकरण होगा। हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कार्यकुशलता बढ़ाएंगे, केन्द्रीयकृत डाटाबेस बनेगा और इसमें पंजीकरण का पूरा प्रावधान है। नौकरशाही से संबंधित मुद्दों से निपटने का भी प्रावधान है। ऑडिट का प्रावधान हम लोग राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आखिर में सारी प्रॉपर्टी की अथॉरिटी राज्य सरकार की है। नियुक्ति बोर्ड का गठन राज्य सरकार करेगी, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है। केन्द्र सरकार कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं ले रही है। सब कुछ राज्य सरकार के अधीन है।

यह कानून किसी की जमीन छीनने वाला नहीं

तीन उद्देश्यों अर्थात् धार्मिक, चैरिटेबल और पवित्र कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड सृजन होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुसलमानों में जो भी जो वक्फ के अंदर अपनी प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से चलाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यह कानून किसी की जमीन छीनने वाला नहीं है, यह कानून किसी हक और उसकी संपत्ति को हड़प करने वाला नहीं है। विधेयक में प्रावधान रखा है कि जब कोई भी मुसलमान वक्फ क्रिएट करता है, तो सबसे पहले उस परिवार की महिला का जो अधिकार है, उसको सुरक्षित करके ही वह वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। आप उसी संपत्ति को ही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका 100 प्रतिशत हिस्सा है।

हमने समिति के सुझाव को मानते हुए कलेक्टर के ऊपर के अधिकारी को इस मामले के लिए प्राधिकृत किया है। आदिवासियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेडयूल 6 में वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण में तीन सदस्यों को शामिल करने, उनका कार्यकाल निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है ताकि विवाद का शीघ्र निस्तारण हो। वार्षिक अंशदान संबंधी समिति के सुझावानुसार मुतवल्ली के लिए अंशदान को 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया, ताकि चैरिटेबल कार्यों पर अधिक धन खर्च किया जाए। सेक्शन 40 के क्रूर प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ■

पृष्ठ 21 का शेष...

इस बात पर जोर दिया कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को जब्त नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उनका प्रबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक कल्याण के लिए जिम्मेदारी से किया जाए।

संवैधानिक और कानूनी चिंताएं

श्री नड्डा ने 2013 के वक्फ अधिनियम में संवैधानिक उल्लंघनों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं:

क. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): अधिनियम ने वक्फ बोडों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के एकतरफा रूप से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की अनुमति दी।

ख. अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): इसने नागरिकों को वक्फ बोर्ड के निर्णयों को सिविल न्यायालयों में चुनौती देने के अधिकार से वंचित कर दिया तथा वक्फ न्यायाधिकरणों में शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया।

ग. अनुच्छेद 300 ए (संपत्ति अधिकार): यह 2013 अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत संपत्तियों को मनमाने ढंग से जब्त करने का अधिकार देता है।

उन्होंने कहा कि संशोधन में इन मुद्दों का समाधान किया गया है, जिसमें कलेक्टरों को वक्फ दावों को सत्यापित करने, जनजातीय भूमि (अनुसूची 5 और 6 के तहत) की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि सरकारी/स्वायत्त निकाय की संपत्तियों (जैसे एएसआई स्मारकों) को वक्फ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

वक्फ संपत्तियों का दस्तावेजी दुरुपयोग

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कुप्रबंधन के खतरनाक उदाहरणों का हवाला दिया जैसेकि 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 5,970 सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। कर्नाटक में 1975 और 2020 के बीच 10 सरकारी संपत्तियों (झीलों, मंदिरों और कृषि भूमि सहित) को वक्फ संपत्तियों में बदल दिया गया।

श्री नड्डा ने यह भी कहा कि सीएजी की 2018 की रिपोर्ट में अनधिकृत भूमि अधिग्रहण और जवाबदेही की कमी सहित प्रणालीगत खामियों को उजागर किया गया है।

सहयोग और चिंतन का आह्वान

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया कि वे इस विधेयक का समर्थन करें, ताकि हाशिए पर रह रहे मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने भू-माफियाओं को वक्फ संपत्तियों का शोषण करने की छूट दी और यह संशोधन ऐसे कमजोर वर्गों की रक्षा करता है, जिनमें महिलाओं से संबंधित विरासत के मुद्दों को भी संबोधित किया गया है।

उन्होंने हाल के चुनावों में मतदाताओं द्वारा विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार करने का हवाला देते हुए विनम्रता और सहयोग की अपील के साथ अपने भाषण का समापन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सांसदों से पक्षपातपूर्ण एजेंडों पर राष्ट्रीय प्रगति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। ■

भारत के शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन के पीछे की सच्चाई

धर्मेन्द्र प्रधान

एक पक्षपातपूर्ण सोच से प्रेरित होकर यह धारणा बनाई जा रही है कि मोदी सरकार के पिछले ग्यारह वर्षों में हमारी शिक्षा प्रणाली पटरी से उतर गई है। वास्तव में, इससे अधिक विडंबनापूर्ण एवं असत्य और कुछ भी नहीं हो सकता। जिस देश ने पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा शिक्षा प्रणाली की घोर उपेक्षा देखी है, वह सच्चाई से पूर्ण रूप से वाकिफ है। एक वह समय भी था जब दुनिया भर के राष्ट्र तेजी से विकसित होती दुनिया के अनुरूप अपनी शिक्षा प्रणाली का विकास कर रहे थे, वहीं भारत का शैक्षिक ढांचा समय के कुचक्र में फंस गया था। हमारी शिक्षा प्रणाली में आखिरी प्रमुख नीतिगत सुधार 1986 में हुआ था, जिसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया। यह औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित एक सोची-समझी साजिश थी, जो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं को कमजोर करके देखती थी, साथ ही इसी सोच ने तेजी से बदलती तकनीकी विकास से देश को वंचित रखा।

पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार एवं कुशासन देश के शैक्षिक ढांचें की विशेषताएं बन गये थे। जहां एक ओर सार्वजनिक विश्वविद्यालय धन की कमी का सामना कर रहे थे, वहीं गैर मान्यता प्राप्त निजी संस्थान डिग्री मिलों में बदल गए थे। जो लोग सीमित सोच रखते हैं, उन्हें 2009 का 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोटाला याद दिलाने की आवश्यकता है, इसके सामने आने के बाद पता चला कि कैसे 44 निजी संस्थानों को उचित मूल्यांकन के बिना विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था, जिनमें से कई बाद में वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाए गए। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। विश्वविद्यालय के पदों की नियुक्तियां राजनीतिक निष्ठा के आधार पर होती थीं। पाठ्यपुस्तकों में जानबूझकर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों के योगदान को कम करके आंका गया, जबकि विदेशी आक्रमणों के बारे में असहज ऐतिहासिक सत्यों को चित्रित किया गया। राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक आख्यानों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। भारत की विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया। इन सभी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को तैयार किया जो हमारे गौरवशाली अतीत के एक दम विपरीत थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 इस कलंकपूर्ण अतीत पर पूर्णविराम लगाने का प्रयास करती है। यह भारत के इतिहास में सबसे व्यापक लोकतांत्रिक परामर्श का परिणाम है। प्रमुख वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन ने इस टीम का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लाखों हितधारकों से विचार-विर्मश किया। देखा जाए तो पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं जवाबदेही के पांच स्तंभों पर आधारित 'एनईपी 2020' लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के भविष्य के लिए एक नीति है।

एनईपी 2020 का एक प्राथमिक उद्देश्य असमानताओं को ठीक करना है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप 2014-15 से उच्च शिक्षा में एससी उम्मीदवारों के नामांकन में 50 प्रतिशत, एसटी में 75 प्रतिशत और ओबीसी में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आवासीय विद्यालयों ने साक्षरता दर में वृद्धि की है और आदिवासी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति ने उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाया है।

शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता में अभूतपूर्व प्रगति के साथ महिला सशक्तीकरण इन सुधारों के केंद्र में है। सभी श्रेणियों में महिला उम्मीदवारों के नामांकन में 38.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2022-23 में 2.18 करोड़ को पार कर गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रों में महिला नामांकन में 57.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10 और 12 में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या में क्रमशः 72 प्रतिशत और 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के बीच पीएचडी नामांकन में 135 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उच्च शिक्षा STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) क्षेत्रों में अब महिलाओं की संख्या 43 प्रतिशत है, इस प्रकार पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। शिक्षण कार्यबल में

महिलाओं की भागीदारी 44.23 प्रतिशत हैं, जो 2014 में 38.6 प्रतिशत थी। यह सभी मानक भारत के शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक मौलिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। वहीं अब महिलाएं हमारे देश की बौद्धिक यात्रा में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त कर रही हैं।

ये कदम हमारी प्राथमिकताओं में एक मौलिक बदलाव को दर्शाते हैं। ऐसे ही प्रति बच्चा सरकारी व्यय 2013-14 के 10,780 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 25,043 रुपये हो गया, यह बढ़ोतरी 130 प्रतिशत की है। सरकार बच्चों के समग्र एवं संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, समग्र शिक्षा और अन्य सहायता प्रणाली के साथ उन्नत किया जा रहा है। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या और साथ ही ड्रॉप-आउट दरों में कमी आई है; छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है; और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखने की प्रक्रिया में लगातार सुधार हो रहा है।

एनईपी 2020 ने मध्य विद्यालय स्तर से कोडिंग, समस्या-समाधान के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार केंद्र जैसी भविष्यपरक पहलों की शुरुआत की है। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। 3,000 से अधिक कौशल विकास केंद्र शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाट रहे हैं। ये पहल भारत के भविष्य के लिए शिक्षा की एक मौलिक पुनर्कल्पना का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे युवा पुराने घोषणापत्र और पुराने नारों से ज्यादा के हकदार हैं। सरकार की योजना अगले पांच सालों में स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 50,000 और एटीएल स्थापित करने की है।

उच्च शिक्षा में स्थायी राजस्व मॉडल ने विश्वविद्यालयों को संसाधनों पर निर्भरता से मुक्त कर दिया है। भारत के अब 11 विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड रैंकिंग के शीर्ष 500 में हैं, जो कि अतीत की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। 2015 से शोध प्रकाशनों में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2014 में 76वें स्थान पर था। अनुसंधान— राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत एक उभरती हुई ज्ञान अर्थव्यवस्था और सीखने के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति ने उन सभी भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं की गरिमा को बहाल किया है, जो दशकों से चली आ रही 'अंग्रेजी-प्रथम' नीतियों के कारण पीछे रह गयी थी। भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) पहल के माध्यम से 8,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों ने आईकेएस पाठ्यक्रम को अपनाया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के माध्यम से 22 भारतीय भाषाओं में 15,000 मूल और अनूदित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी, जिससे लाखों युवा को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का लाभ मिलेगा।

एनईपी 2020 ने मध्य विद्यालय स्तर से कोडिंग, समस्या-समाधान के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार केंद्र जैसी भविष्यपरक पहलों की शुरुआत की है

सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधिनियमन से परिलक्षित हुई, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण पदों के आरक्षण के लिए 'संस्था को एक इकाई' के रूप में माना गया, न कि 'प्रत्येक विभाग को एक इकाई' के रूप में मानने की घोर दोषपूर्ण प्रणाली को जारी रखा गया। इसी तरह, सरकार ने आरक्षण को वास्तव में सार्थक बनाने के लिए विश्वविद्यालय भर्तियों में एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए 'कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया' घोषित करने और इन्हें गैर-आरक्षित पदों के रूप में परिवर्तित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया।

ये उपलब्धियां लाखों सशक्तीकरण की गाथाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओडिशा की एक आदिवासी लड़की गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रही है, राजस्थान में पहली पीढ़ी की एक छात्रा उन्नत शोध कर रही है, तमिलनाडु में एक छात्रा अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है— ये सब उस नीति के वास्तविक परिणाम हैं जो शिक्षा को राष्ट्रीय परिवर्तन की एक शक्ति के रूप में देखती है।

हमारी सरकार एक ऐसे 'विकसित भारत' के निर्माण पर केंद्रित है, जहां शिक्षा वास्तव में मुक्ति और सशक्तीकरण प्रदान करती है। आने वाला दशक एक शैक्षिक पुनर्जागरण का गवाह बनेगा, जो हमारे अतीत का सम्मान करते हुए निडरता से भविष्य को गले लगाएगा। भारत की शिक्षा प्रणाली अंततः औपनिवेशिक छाया और वैचारिक कैद से मुक्त हो गई है। यह अब न केवल लाखों भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है, बल्कि दुनिया को एक ऐसा मॉडल पेश करने के लिए तैयार है जो परंपरा को नवाचार, समावेश को उत्कृष्टता और राष्ट्रीय गौरव को वैश्विक प्रासंगिकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यह केवल शिक्षा सुधार नहीं है— यह बौद्धिक उपनिवेशवाद का उन्मूलन है जिसका भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा है जो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचा देगा। ■

(लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं)

अटलजी: भारतीय राजनीति का निर्लिप्त कमल भाव

देश की राजनीति में साफ-सुथरे मन के महामनीषी अजातशत्रु आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का विरोधी दल के नेता भी बेहद सम्मान करते थे। वे निष्पक्ष राजनीति के कबीर की कोटि के अवधूत संत की तरह थे। लोगों के हित और कल्याण पर हमेशा करुणा से भरे रहने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश में सभी वर्गों के चहेते थे

बृजमोहन अग्रवाल

अटल बिहारी वाजपेयीजी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर और आगरा के नजदीक मध्य प्रदेश के बटेश्वर में एक कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मां कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयीजी थे। उनके पिता ग्वालियर में एक स्कूल शिक्षक थे। अटल जी के मुख में साक्षात् सरस्वती विराजमान थीं तभी तो उनका भाषण सुनने के लिए लोग कई-कई किलोमीटर दूर से चले आते थे। अपने छात्र जीवन में वे एक बार प्रयागराज विश्वविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रतियोगी के रूप में काफी विलंब से पहुंचे और प्रतियोगिता लगभग खत्म होने वाली थी, तभी आयोजकों से अंत में अपनी डिबेट सुनने भर का मनुहार किया था। तब प्रतियोगिता के अंत की औपचारिकता पूरी करते हुए आयोजकों ने अटलजी को बोलने का अवसर दिया और फिर बाद में अटलजी ने अपनी वाक् कला कौशल और धाराप्रवाह अभिव्यक्ति की वजह से प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का इनाम जीत लिया था। तो ऐसे थे अपने अटलजी।

संसद में उनके भाषण अक्सर पंडित नेहरू भी पसन्द करते थे और कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयीजी एक दिन देश के बड़े राजनयिक बनेंगे। 1977 की जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका हिन्दी भाषण आज भी समूची दुनिया में भारतीय सभ्यता और हिंदी संस्कृति का एक सटीक प्रमाण है। राजनीति में ज्यों की त्यों धर दीन्हीं चदरिया का व्यक्तित्व विरले ही कायम कर पाते हैं।

भारतीय राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जिस तरह जिया है, वह तो वास्तव में अनुकरणीय, अद्भुत, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय है। अटल बिहारी वाजपेयीजी में साहित्य और पत्रकारिता का बेहद सृजनात्मक संजोग था। ऐसे अनुपम संजोग के साथ जब वे राजनीति में आए तो उनके अंदर लोगों के आम दुःख-दर्द को समझने के लिए एक बहुत बड़ी चेतना अपने आप विकसित होने लगी।

अटल बिहारी वाजपेयीजी का गांव बटेश्वर कभी डाकुओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार को बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयीजी के जन्मस्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देना चाहिए।

1996 के दशक में 24 दलों की गठबंधन सरकार में 81 मंत्रियों का केंद्र सरकार में कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने देश की राजनीति को गठबंधन धर्म निभाते हुए धैर्य और धर्म के साथ नैतिकता का पाठ पढ़ाया। ऐसे समन्वय और गठबंधन धर्म के दौर में अटल बिहारी वाजपेयीजी को जयललिता, ममता बनर्जी और मायावती जैसी महिला राजनीतिज्ञों की चपल और चंचल राजनीति का सामना करना पड़ा। तीनों महिला राजनीतिज्ञों के साथ बेहद समन्वय स्थापित करते हुए अटलजी ने भारतीय राजनीतिक परंपरा में गठबंधन धर्म की एक नई मिसाल कायम की, जो आज भी नेताओं के लिए एक सीख हो सकती है।

1999 के दौर में अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार महज एक वोट से गिर गई थी। तब सदन में निराश अटलजी ने कहा था कि भाजपा का भी समय आएगा। मुझे लगता है कि वर्तमान का यह समय भाजपा का वही समय है, जिसकी भविष्यवाणी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने करीब 26 साल पहले की थी। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भाजपा अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद 1996 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का धीरे-धीरे उत्थान होने लगा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब थी और बहुमत की तलाश कर रही थी तब सदन में मराठा नेता और आज लगभग हाशिये पर आ चुके शरद पवार ने अटलजी पर व्यंग्य कसते हुए कहा था कि ऐसे तो अटलजी ने कभी शादी नहीं की और अब जब वह (प्रधानमंत्री) दूल्हा बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके पास बाराती की यानी बहुमत की कमी है। अटलजी ऐसे व्यंग्य और ताने सहते हुए भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए और लगातार कोशिश करते हुए सदन में सरकार बनाते हुए भाजपा और देश को नई दिशा दी। यह अटल बिहारी वाजपेयीजी की ही सेवा भावना का भाजपा को सुनहरा आशीर्वाद है कि अब भाजपा देश की नियति बनती जा रही है। वाजपेयीजी केवल पांच-छह साल के कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिससे देश में आर्थिक वृद्धि और विकास को नया आयाम मिला।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना

अटल बिहारी वाजपेयीजी ने 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भारत में असंबद्ध गांवों

को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 500 या अधिक जनसंख्या वाले गांवों को हर मौसम में सड़क से जोड़ना था।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क विहीन गांवों को सड़क मार्ग से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाना और विकास को बढ़ावा देना था।

नदी जोड़ो परियोजना

अटल बिहारी वाजपेयीजी ने भारत में नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सूखा क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाना, बाढ़ और सूखे को कम करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना और जलविद्युत उत्पादन को बढ़ावा देनी की सोची थी। जल-अधिशेष नदियों को जल-अभावग्रस्त नदियों से जोड़कर, यह परियोजना जल संसाधनों को संतुलित करने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। अटल बिहारी वाजपेयीजी की 100वीं जयंती पर 44,600 करोड़ की लागत वाली देश की पहली केन-बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मध्यप्रदेश के खजुराहो में शिलान्यास किया। इसी के साथ ही देश की यह पहली नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयीजी के मध्यप्रदेश के नाम हो गई।

पोखरण परमाणु परीक्षण

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व में 11 और 13 मई, 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में कुल पांच परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण 1974 में हुआ था। इन परीक्षणों के बाद भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया गया। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य भारत को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करना था।

इन परीक्षणों में 45 किलोटन का एक तापीय परमाणु उपकरण (हाइड्रोजन बम) और 15 किलोटन का एक विखंडन उपकरण (फिशन बम) शामिल थे। इन परीक्षणों के बाद भारत दुनिया में परमाणु हथियार संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। इन परीक्षणों के बाद कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत इन प्रतिबंधों से नहीं झुका। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इन परीक्षणों के माध्यम से भारत की परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया और देश में गर्व की भावना पैदा की।

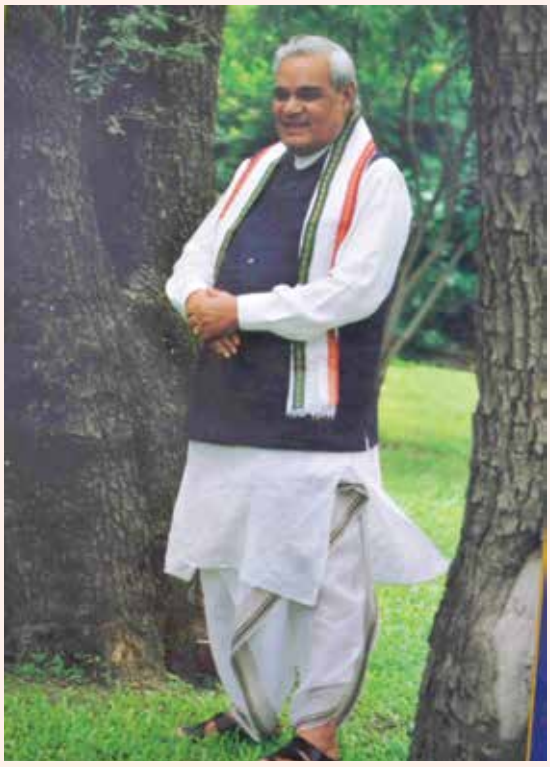

इन परीक्षणों में तत्कालीन वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान प्रमुख रूप से शामिल था।

इसके अलावा फिल्म अभिनेताओं और रंगकर्मियों के साथ पाकिस्तान की राजनयिक यात्रा दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को एक नया कलेवर दिया बस से लाहौर तक की यात्रा अटल बिहारी वाजपेयीजी के कवि हृदय की एक सुनहरी दास्तान हो सकती थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के तानाशाह सैन्य प्रशासक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा आगरा शिखर वार्ता को छोड़ स्वदेश पाकिस्तान जाने की घटना आज भी अटलजी के अंदर के एक बेहद सुलझे राजनयिक की तस्वीर को अमन-चैन के प्रेमी एक आम भारतीय अपने हृदय में स्थापित किए हुए हैं।

कमल सा सदैव निर्लिप्त रहने की लहलहाती ललक

देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पवित्र प्रतीक के रूप में रोटी और कमल को जन समूह में बतौर प्रतीक पेश किया गया था। कमल का यह पुष्प इस संसार में लोभ और मोह माया के बीच भी निर्लिप्त होने का एक शाश्वत प्रतीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमल के फूल पर जल की बूंदें डालने से फूल गीला नहीं होता है, अपितु जल की बूंदें कमल पर पड़ते ही निर्लिप्त भाव से गोल मोतियों का रूप लेकर फूल से अलग होते हुए ढल जाया करती हैं। जो निर्लिप्त भाव यानी सांसारिक चीजों से अलगाव यानी आसक्ति से कहीं दूर एक पवित्र मुक्त भाव के संकेत देती हैं। ऐसा ही पवित्र कमल फूल कालांतर में भाजपा का प्रतीक बना। जो अपनी निर्लिप्तता की व्याख्या करता हुआ आज भाजपा को भी देश के लोकतंत्र में जनता-जनार्दन के हितों के लिये सबसे सक्रिय और आसक्ति से दूर यानी निर्लिप्त भाव से लोक सेवा करने की ताकीद लगातार दे रहा है। जीवन भर अविवाहित रहते हुए आम जन मानस की सेवा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयीजी सादे और लोक-लुभावन जीवन जीकर समूची भाजपा को राजनीति के निर्लिप्त कमल भाव से जीवन पर्यंत सराबोर करते रहे और भविष्य में भी करते रहेंगे। ■

(लेखक छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर के भाजपा सांसद और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से विकास का एक दशक

जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा और वित्तीय समावेशन का विस्तार

8 अप्रैल, 2025 को भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वित्तपोषण से वंचित सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना है। कोलेटरल के बोझ को हटाकर और पहुंच को सरल बनाकर, मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी

अप्रैल, 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए हैं। इससे देश भर में उद्यमिता की क्रांति को बढ़ावा मिला है। व्यापार वृद्धि अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। यह छोटे शहरों और गांवों तक फैल रही है, जहां पहली बार उद्यमी अपनी नियति को साकार कर रहे हैं। मानसिकता में बदलाव स्पष्ट है— लोग अब रोजगार चाहने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि वे रोजगार देने वाले बन रहे हैं।

एमएसएमई ऋण की धूम: कारोबार का एक सशक्त इको-सिस्टम

एसबीआई की रिपोर्ट में मुद्रा योजना के प्रभाव से एमएसएमई को ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। ऋण वित्त वर्ष 2014 में एमएसएमई के लिए 8.51 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 27.25 लाख करोड़ रुपये हो गया और वित्त वर्ष 2025 में 30 लाख करोड़ रुपये को पार करने का अनुमान है। बैंक के कुल ऋण में एमएसएमई ऋण की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014 में 15.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में लगभग 20 प्रतिशत हो गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस विस्तार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों को वित्तीय सहायता तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। जो पहले उपलब्ध नहीं थी, जिससे भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।

वित्तीय समावेशन: महिलाओं का सशक्तीकरण

मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13 प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपये हो गई। ऋण वितरण में महिलाओं की अत्यधिक हिस्सेदारी वाले राज्यों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के माध्यम से काफी अधिक रोजगार सृजन किया है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में लक्षित वित्तीय समावेशन की प्रभावशीलता को मजबूत करता है।

वित्तीय समावेशन: सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों तक पहुंच

पीएमएमवाई ने पारंपरिक ऋण बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत मुद्रा खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के पास हैं, जिससे औपचारिक वित्त तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, मुद्रा ऋण धारकों में से 11 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनने में सक्षम बनाकर समावेशी विकास में योजना के योगदान को दर्शाता है।

प्रगतिशील ऋण: शिशु से तरुण तक

पिछले दस वर्षों में मुद्रा योजना ने 52 करोड़ से ज्यादा लोन खाते खोलने में मदद की है, जो उद्यमशीलता की गतिविधियों में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। किशोर लोन (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए) की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 44.7 प्रतिशत हो गई है, जो सूक्ष्म से छोटे उद्यमों की ओर बदलाव को दर्शाता है। तरुण श्रेणी (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए) भी तेजी से बढ़ रही है, जो साबित करती है कि मुद्रा योजना सिर्फ व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में मदद भी करती है।

अधिक ऋण, सशक्त कारोबार

पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित कुल ऋणों पर नजर डालने से पता चलता है कि इस योजना के विशिष्ट विक्रय प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के इच्छित लाभार्थियों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है, जिससे समाज के निचले तबके के आर्थिक विकास को मजबूती मिली है।

ऋणों का औसत आकार लगभग तीन गुना बढ़ गया है; वित्त वर्ष 2016 के 38,000 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 72,000 रुपये और वित्त वर्ष 2025 में 1.02 लाख रुपये हो गया है, जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में इसके योगदान और बाजार पर प्रभाव दोनों को दर्शाता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 23 में ऋण वितरण में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पूरे देश में उद्यमशीलता के प्रति विश्वास के जोरदार पुनरुद्धार

का संकेत है।

पीएम मुद्रा योजना के ऋण वितरण में अग्रणी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से 28 फरवरी, 2025 तक तमिलनाडु ने 3,23,647.76 करोड़ रुपये के साथ राज्यों में सबसे अधिक वितरण दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश 3,14,360.86 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 3,02,146.41 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी क्रमशः 2,82,322.94 करोड़ रुपये और 2,81,943.31 करोड़ रुपये का वितरण हुआ है। महाराष्ट्र 2,74,402.02 करोड़ रुपये के साथ छठे स्थान पर है, जो पिछले एक दशक में प्रमुख राज्यों में योजना की व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे है, जहां 21,33,342 ऋण खातों में 45,815.92 करोड़ रुपये का कुल वितरण किया गया है। ये आंकड़े न केवल राज्यों में बल्कि केंद्रशासित प्रदेशों में भी ऋण तक पहुंच बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका को दर्शाते हैं।

वित्तपोषण से वंचित को वित्तपोषण

सूक्ष्म उद्यम हमारे देश में एक प्रमुख आर्थिक खंड हैं और कृषि के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं। इस खंड में विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में लगी सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं। यह लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इनमें से कई इकाइयां मालिकाना/एकल स्वामित्व या स्वयं के खाते वाले उद्यम हैं और कई बार इन्हें गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है।

पीएमएमवाई का मिशन, विजन और उद्देश्य

योजना की मुख्य विशेषताएं

सूक्ष्म उद्यम इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्तपोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह सुनिश्चित करती है कि सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 20 लाख रुपये तक का कोलेटरल-फ्री संस्थागत ऋण प्रदान किया जाए।

इस योजना के अंतर्गत क्रियाकलाप की तीन श्रेणियां तैयार की गई हैं, जिनमें शामिल है:

तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण (विशेष रूप से तरुण श्रेणी के लिए डिजाइन किए गए, जिन्होंने पहले ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में वित्तीय पहुंच बढ़ाने और समावेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के प्रभाव को लगातार स्वीकार किया है।

2017 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उल्लेख किया कि यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्त तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों को कोलेटरल-फ्री ऋण प्रदान करके बैंकिंग सुविधा से वंचित परिवारों पर पीएमजेडीवाई के फोकस को पूरा करता है।

2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पीएमएमवाई की सराहना करते हुए कहा कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के तहत यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे व्यवसायों को ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों का समर्थन करके सूक्ष्म उद्यमों को विकसित करने और पुनर्वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2023 तक पीएमएमवाई की कोलेटरल-फ्री ऋण संरचना, महिला उद्यमिता पर केन्द्रित करने के साथ, महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जो अब 2.8 मिलियन से अधिक है।

अपनी 2024 की रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पुनः पुष्टि की कि पीएमएमवाई जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता के लिए भारत का सक्षम नीतिगत वातावरण, ऋण तक पहुंच के माध्यम से स्वरोजगार और औपचारिकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

निष्कर्ष

दस वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लगातार वित्तीय समावेशन की शक्ति और जमीनी स्तर पर नवाचार की ताकत का प्रदर्शन किया है। 2014 से पहले ऋण तक पहुंच अक्सर अच्छी तरह से जुड़े लोगों के पक्ष में थी, जबकि छोटे उद्यमियों को जटिल कागजी कार्रवाई जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता था या उन्हें अनौपचारिक वित्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बैंकों ने बड़ी कंपनियों को लापरवाही से ऋण दिया, जबकि वास्तविक ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण तक पहुंच नहीं मिल पाई। मुद्रा ने इस शून्य को भरते हुए एक स्वच्छ, समावेशी विकल्प पेश किया, जिसने सभी को समान अवसर दिया।

52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत होने के साथ इस योजना ने औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाकर महिलाओं, अजा/अजजा/अपिब समुदायों और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाया है। ऋण के औसत आकार में वृद्धि, एमएसएमई ऋण की बढ़ती हिस्सेदारी और सूक्ष्म से लघु उद्यमों की ओर बदलाव इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। पीएमएमवाई न केवल स्वरोजगार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है और समान विकास को आगे बढ़ा रहा है। ■

मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से की बातचीत

इस योजना के तहत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं और इससे 50% एससी/एसटी/ओबीसी उद्यमी लाभान्वित हुए हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ अप्रैल को नई दिल्ली में 7, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने और पूरे भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर मुद्रा योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे इस योजना ने हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे उन्हें बिना किसी गारंटी या व्यापक कागजी कार्रवाई के अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया गया है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना ने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाया है, बल्कि उनके लिए अपने व्यवसायों का नेतृत्व करने और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर भी पैदा किए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के सबसे अधिक लाभार्थियों में महिलाएं हैं, जो ऋण आवेदनों, अनुमोदनों और तेजी से पुनर्भुगतान में अग्रणी हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत भारत के नागरिकों को बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह राशि अभूतपूर्व है और सामूहिक रूप से धनी व्यक्तियों को दी गई किसी भी वित्तीय सहायता से कहीं अधिक है। श्री मोदी ने देश के प्रतिभाशाली युवाओं पर अपना भरोसा जताया, जिन्होंने रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।

श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से रोजगार सृजन ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकते हैं। उन्होंने इस योजना से होने वाले सामाजिक लाभों को भी स्वीकार किया।

मुद्रा ऋण का दायरा बढ़ाने में सरकार द्वारा प्रदर्शित उल्लेखनीय विश्वास पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रारंभ में 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के ऋण का दायरा बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह विस्तार भारत के नागरिकों की उद्यमशीलता की भावना और क्षमताओं में व्यक्त विश्वास को दर्शाता है, जो योजना के सफल कार्यान्वयन से और मजबूत हुआ है।

मुद्रा योजना का लाभ उठाने और अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने लोगों से कम से कम पांच से दस अन्य लोगों को प्रेरित करने और उनका समर्थन करने, उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 52 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं, जो विश्व स्तर पर एक अद्वितीय उपलब्धि है।

मुद्रा योजना के 10 वर्ष सशक्तीकरण और उद्यमशीलता के प्रतीक रहे हैं: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए इसे 'सशक्तीकरण और उद्यमशीलता' की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि सही समर्थन से भारत के लोग चमत्कार कर सकते हैं।

अपनी शुरुआत से अब तक मुद्रा योजना ने 33 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से ज़्यादा जमानत-मुक्त ऋण वितरित किए हैं, जिनमें से लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं और इससे 50% एससी/एसटी/ओबीसी उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। इसने पहली बार व्यवसाय करने वाले मालिकों को 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण के साथ सशक्त बनाया है और पहले तीन वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा की हैं। लगभग 6 करोड़ ऋणों की स्वीकृति के साथ, बिहार जैसे राज्य अग्रणी बनकर उभरे हैं, जिससे पूरे भारत में उद्यमशीलता की मजबूत भावना पता चलती है। ■

'रामेश्वरम के लिए नया पंबन ब्रिज प्रौद्योगिकी और परंपरा को एक साथ लाता है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छह अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज- नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई और पुल का संचालन देखा। उन्होंने रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा भी की।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज श्रीरामनवमी का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि आज ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर में सूर्य की दिव्य किरणों ने रामलला को भव्य तिलक से सुशोभित किया। श्री मोदी ने कहा, "भगवान श्रीराम का जीवन और उनके शासनकाल से मिली सुशासन

की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार का काम करती है।" उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के संगम युग के साहित्य में भी भगवान श्रीराम का उल्लेख है, उन्होंने रामेश्वरम की पवित्र धरती से श्रीरामनवमी के अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल

यह देखते हुए कि रामेश्वरम भारत रत्न डॉ. कलाम की भूमि है, जिनके जीवन ने दिखाया कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, "रामेश्वरम के लिए नया पंबन पुल प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिलन का प्रतीक है।" श्री मोदी ने कहा कि यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो बड़े जहाजों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता है और साथ ही तेज़ ट्रेन यात्रा को सक्षम बनाता है। उन्होंने आज एक नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को हरी झंडी दिखाने का उल्लेख किया और इस उल्लेखनीय परियोजना के लिए तमिलनाडु के लोगों को बधाई दी।

इस बात को रेखांकित करते हुए कि इस पुल की मांग कई दशकों से चली आ रही थी, श्री मोदी ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से इस कार्य को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पम्बन पुल व्यापार करने में आसानी और यात्रा में आसानी दोनों का समर्थन करता है, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नई ट्रेन सेवा रामेश्वरम से चेन्नई और देश के अन्य हिस्सों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस विकास से तमिलनाडु में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

श्री मोदी ने कहा, "पिछले 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो गया है"। उन्होंने इस कहा कि इस तीव्र वृद्धि का एक प्रमुख कारण देश का उल्लेखनीय आधुनिक बुनियादी ढांचा है। उन्होंने बल देकर कहा कि पिछले दशक में रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, पानी और गैस पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढांचे के लिए बजट में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है।

आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि मजबूत, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के अथक प्रयासों से प्रेरित है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश के लोग भाजपा सरकारों के सुशासन और राष्ट्रहित में लिए जा रहे निर्णयों को देख रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के हर राज्य और कोने में भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन सहित अन्य लोग मौजूद थे। ■

बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता क्रमशः लगभग 118 और 119 प्रतिशत रही

संसद के दोनों सदनों द्वारा 16 विधेयक पारित किए गए

31 जनवरी, 2025 से प्रारंभ हुआ संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल, 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने चार अप्रैल को संसद के बजट सत्र, 2025 की समाप्ति के बाद पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे।

श्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं।

वर्ष का पहला सत्र होने का कारण राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों में संयुक्त संबोधन किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पेश किया और श्री रविशंकर प्रसाद ने इसका समर्थन किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावों पर सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों द्वारा प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद चर्चा की गई और उन्हें अपनाया गया।

वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किया गया। सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई।

सत्र के दूसरे भाग के दौरान रेलवे, जल शक्ति और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और लोकसभा में मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को 21 मार्च, 2025 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21 मार्च, 2025 को ही लोकसभा में पेश किया गया, उस पर विचार किया गया और उसे पारित कर दिया गया।

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक, वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें और वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर की अनुदानों की अनुपूरक मांगें और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2025-26 के लिए लेखानुदान की मांगों को भी लोकसभा में 11 मार्च, 2025 को पारित किया गया।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित

संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तीकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। जबकि मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को भी निरस्त कर दिया गया।

इस सत्र के दौरान कुल 11 विधेयक (लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 1) प्रस्तुत किए गए। 16 विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए और 14 विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित/वापस किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 16 विधेयक पारित किए गए।

बजट सत्र, 2025 के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 118 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 119 प्रतिशत थी।

दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2025
- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2025
- विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025
- विनियोग विधेयक, 2025
- मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025
- मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025
- बॉयलर विधेयक, 2025
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
- विनियोग विधेयक (3), 2025
- वित्त विधेयक, 2025
- त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
- आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025 ■

अब 'अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस' ने एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 मार्च को 'मन की बात' संबोधन में दैनिक जीवन में फिटनेस के महत्व पर जोर दिया और फिट इंडिया कार्निवल तथा अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहलों की प्रशंसा की। स्वस्थ विश्व के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "योग दिवस 2025 की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' रखी गई है। यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं।"

देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सोक पिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 'कैच द रेन' अभियान के लिए कमर कस ली गई है

लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम के 120वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, "आज फिटनेस के साथ-साथ गिनती भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक दिन में कितने कदम चले, एक दिन में कितनी कैलोरी खाई, कितनी कैलोरी बर्न कीइन सब गिनतियों के बीच एक और उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय बचा है। अगर आपने अभी तक योग को अपने जीवन में शामिल नहीं किया है, तो अभी करें अभी भी देर नहीं हुई है।"

श्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले 21 जून, 2015 को पहला अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है, जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे योग और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा योग और आयुर्वेद को स्वास्थ्य के एक बेहतरीन माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। अब जैसे दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। वहां आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पिछले साल ब्राजील की अपनी यात्रा के दौरान मैंने चिली के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। आयुर्वेद की लोकप्रियता को लेकर हमारी काफी चर्चा हुई थी।"

दुनिया भर में आयुष प्रणालियों की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता

दुनिया भर में आयुष प्रणालियों की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता और इसमें प्रमुख हितधारकों के योगदान को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे 'सोमोस इंडिया' नाम की एक टीम के बारे में पता चला है। स्पेनिश में इसका मतलब है, 'हम भारत हैं'। यह टीम लगभग एक दशक से योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। उनका ध्यान इलाज के साथ-साथ शैक्षणिक कार्यक्रमों पर भी है। वे योग और आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियों का स्पेनिश भाषा में अनुवाद भी करवा रहे हैं। अगर पिछले साल की ही बात करें तो उनके असंख्य कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में लगभग 9 हज़ार लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं इस टीम से जुड़े सभी लोगों को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।"

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर-शहर, गांव-गांव पानी बचाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अनेक राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों ने, जल संरक्षण से जुड़े कामों ने नई तेजी पकड़ी है। जलशक्ति मंत्रालय और अलग-अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सोक पिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 'कैच द रेन' अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता-जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन-भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं, उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है।

श्री मोदी ने कहा कि जब हम जड़ से जुड़े रहते हैं तो कितना ही बड़ा तूफान आए; तूफान हमें उखाड़ नहीं पाता। आप कल्पना करिए, करीब 200 साल पहले भारत से कई लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरीशस गए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन समय के साथ वे वहां रच-बस गए। मॉरीशस में उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी विरासत को सहेजकर रखा और जड़ों से जुड़े रहे। मॉरीशस ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले साल जब मैं गुयाना गया था तो वहां की चौताल ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी ने नागपुर स्थित रा.स्व.संघ मुख्यालय जाकर डॉ. हेडगेवार और दीक्षाभूमि जाकर डॉ. अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 मार्च, 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर गये और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक श्रद्धेय एमएस गोलवलकर (श्रीगुरुजी) को समर्पित स्मारकों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्मृति मंदिर यात्रा के दौरान रा.स्व.संघ सरसंघचालक श्री मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ प्रचारक भी उपस्थित थे।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दीक्षाभूमि जाकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां भारत के संविधान के निर्माता ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था।

श्री मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।

रा.स्व.संघ मुख्यालय का प्रवास करने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "नागपुर में स्मृति मंदिर की यात्रा एक बहुत ही विशेष अनुभव है। आज की यात्रा को और भी विशेष बनाने वाली बात यह है कि यह वर्ष प्रतिपदा के दिन हुई है, जो परम पूज्य डॉक्टर साहब की जयंती भी है। मेरे जैसे अनगिनत लोग परम पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी के विचारों से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करते हैं। इन दो महानुभावों को श्रद्धांजलि देना सम्मान की बात थी, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली भारत की कल्पना की थी।"

नागपुर में दीक्षाभूमि की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "नागपुर में दीक्षाभूमि सामाजिक न्याय और वंचितों को सशक्त बनाने के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। भारत की पीढ़ियां डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञ रहेंगी, जिन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हमारी गरिमा एवं समानता सुनिश्चित करता है। हमारी सरकार हमेशा पूज्य बाबासाहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चली है और हम उनके सपनों के भारत को साकार करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।" ■

बैंकॉक (थाईलैंड) में 03 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ 'त्रिपिटक' का एक विशेष संस्करण भेंट करतीं थाईलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा

थाईलैंड (बैंकॉक) में 04 अप्रैल, 2025 को आयोजित 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कोलंबो (श्रीलंका) में 05 अप्रैल, 2025 को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कोलंबो (श्रीलंका) में 05 अप्रैल, 2025 को श्रीलंकाई क्रिकेटरों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 01 अप्रैल, 2025 को चिली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री गेब्रियल बोरिक फॉन्ट से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 08 अप्रैल, 2025 को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 19 अप्रैल, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह